● वर्ष-3
● अंक-40
रायपुर, रविवार
24 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› गणेश जी को क्यों प्रिय है मोदक

हरमनप्रीत-लवलीना ने की भारतीय दल की अगुआई

हांगझोऊ एशियाड की रंगारंग शुरूआत

हांगझोऊ। चीन के हांगझोई में एशियाई खेलों का उद्घाटन शनिवार (23 सितंबर) को हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खेलों के आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। दोनों ने परेड में भारतीय दल की अगुआई की। उद्घाटन समारोह से पहले ही कई प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी थीं। समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाग लिया। उनकी मौजूदगी में चीन के इतिहास और उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया। शानदार लेजर शो ने लोगों का मन मोह लिया। खिलाड़ियों की परेड में सबसे पहले अफगानिस्तान के एथलीट आए। भारतीय टीम जब आई तो स्टेडियम गूंज उठा। दर्शकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया।

पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स (ट्विटर के नाम से प्रसिद्ध) पर लिखा, %%एशियाई खेल शुरू हो रहे हैं। मैं भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। खेलों के प्रति भारत का जुनून और प्रतिबद्धता चमकती है क्योंकि हम एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहे हैं। आशा है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलें और प्रदर्शन करके दिखाएं कि सच्ची खेल भावना क्या है।उद्घाटन समारोह से पहले क्रिकेट में महिला टीम और फुटबॉल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं।

संसद में रमेश बिधूड़ी के बेलगाम बोल पर बवाल

लोकसभा अध्यक्ष ने बिधूड़ी से नाराज, भाषा का ध्यान रखने की चेतावनी दी

नई दिल्ली। संसद का विशेष सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया। हालांकि, सत्र के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के एक बयान ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। भाजपा सांसद ने सदन के अंदर अमर्यादित टिप्पणियां कीं। इसके बाद जहां एक ओर भाजपा ने असंसदीय बयान के लिए बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा है, तो वहीं विपक्षी दलों ने भाजपा नेता को संसद से निष्कासित करने की मांग की है।

लोकसभा में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी।

रमेश बिधूड़ी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन लोकसभा में चंद्रयान-3 की सफलता पर बोल रहे थे। इस दौरान बसपा सांसद दानिश अली ने कुछ सवाल उठाए। जिस पर भाजपा सांसद ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दानिश अली ने कहा है कि बिधूड़ी ने ये अमर्यादित बातें उन्हें बोली हैं। इसे लेकर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र भी लिखा है।

बिधूड़ी के विवादित बयान के बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से विवादित हिस्से को हटा दिया गया। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिधूड़ी से बात की। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताई और रमेश बिधूड़ी को भाषा का ध्यान रखने की चेतावनी दी। वहीं, भाजपा ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

दानिश और विपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया

बिधूड़ी के आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अमरोहा सांसद दानिश अली ने अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखा है। इसमें बसपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले को जांच के लिए लोकसभा प्रक्रिया के नियम 222, 226 और 227 के तहत विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का अनुरोध किया है। दानिश ने कहा कि चंद्रयान पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने उनके खिलाफ जो शब्द कहे इससे उन्हें गहरी पीड़ा पहुंची है। उनके खिलाफ बेहद गंदे और अपमानजनक अपशब्द कह गए। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।इसके साथ ही दानिश अली ने लोकसभा अध्यक्ष से भाजपा सांसद के खिलाफ नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। कहा कि देश का माहौल खराब न हो इसलिए इस मामले की जांच का आदेश दिया जाए।

विपक्ष ने की निलंबन की मांग

बसपा सुप्रीमो मायावती ने दानिश अली को अपशब्द कहने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा बिधूड़ी के विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रवार को ही राहुल गांधी सांसद दानिश अली से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में हमारी मोहब्बत की दुकान है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, राजद सांसद मनोज झा, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जेडीयू नेता राजीव रंजन, लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी (शरद गुट) की सुप्रिया सुले जैसे कई नेताओं ने भी बयान की निंदा की है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उन्होंने टीएमसी नेता के साथ मिलकर स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें वह बिधूड़ी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला रही हैं।

दानिश अली के आचरण पर भी सवाल

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आज अपनी पार्टी के सहयोगी रमेश बिधूड़ी की एक अन्य सांसद के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी की निंदा की। लेकिन साथ ही बिधूड़ी के निशाने पर आए सांसद के आचरण की जांच की भी मांग की। बिधूड़ी को बार-बार मायावती की बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली के साथ दुर्व्यवहार और इस्लामोफोबिक अपशब्द कहते देखा गया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें चेतावनी दी। उनकी टिप्पणियाँ रिकॉर्ड से हटा दी गईं। हालांकि, रमेश बिधूड़ी के बयान पर जमकर राजनीतिक बवाल जारी है। दुबे ने कहा कि बिधूड़ी की टिप्पणी सभ्य समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। आज एक्स पर निशिकांत दुबे ने लिखा कि रमेश बिधूड़ी के लोकसभा में दिए बयान को कोई भी सभ्य समाज ठीक नहीं कह सकता, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को सांसद दानिश अली के भी अमर्यादित शब्दों व आचरण की जाँच करनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि लोकसभा की नियम प्रक्रियाओं के तहत किसी सांसद के निर्धारित समय के बीच टोकना, बैठे बैठे बोलना, रनिंग कमेंट्री करना भी सजा के दायरे में आता है।

कागज और अन्य सामग्री की मूर्तियों के बाद, मुंबई की एक डिजाइनर ने भगवान गणेश की चॉकलेट और विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज से मूर्ति तैयार की है। हर साल, दस दिवसीय गणपति उत्सव के लिए लोग सजावट आदि में अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हैं, लेकिन सांताक्रूज़ निवासी रिंटू राठौड़ ने इस बार चॉकलेट, नौ प्रकार के मोटे अनाज और अन्य सामग्री से भगवान गणेश की दो फुट की सुंदर मूर्ति बनाई है। बप्पा की यह मूर्ति वृश्चिकासन मुद्रा में है। डिजाइनर राठौड़ ने कहा, ''इस मुद्रा का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है।

ताम्रध्वज को मुख्यमंत्री नहीं बनाना साहू समाज को धोखा: तेली

नईदिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने शनिवार को दावा कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर साहू समाज का वोट लिया और चुनाव जीतने के बाद साहू की जगह भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया। राज्य के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे। राज्य के रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की परिवर्तन यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और श्रम राज्य मंत्री तेली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने

लोगों से किए वादों को पूरा नहीं किया।असम से सांसद तेली ने कहा कि वह साहू समुदाय से हैं और उनके परिवार की जड़ें इसी क्षेत्र (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) में हैं। केंद्रीय मंत्री तेली ने रैली में कहा, कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू अपने परिवार के साथ असम से विमान में यात्रा कर रहे थे। उसी विमान में हमारे एक सांसद भुवनेश्वर कलिता भी यात्रा कर रहे थे जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं और पिछले चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रहे थे। कलिता ने मुझसे पूछा कि क्या ताम्रध्वज को पहचाना हूं ? मैंने जवाब दिया कि हां, ये छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री हैं।'' उन्होंने दावा किया, ''कलिता ने उन्हें बताया कि पिछले चुनाव में जब वह प्रभारी था तब कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू के नाम पर साहू समाज से वोट लिया और झूठ बोला कि चुनाव जीतने पर ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाएंगे।

चुनाव जीतने के बाद भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया। तेली ने कहा, कलिता जी ने ताम्रध्वज साहू के सामने यह बात कही कि कांग्रेस ने राज्य में साहूओं को धोखा दिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो वादे तो करती है लेकिन उन्हें पूरा करने में विफल रहती है। उन्होंने लोगों से महेश साहू को चुनने का आग्रह किया, जिन्हें पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए खरसिया सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। तेली ने आमसभा को कुछ समय स्थानीय में भी संबोधित किया और कहा कि जब भी उनके घर छत्तीसगढ़ से मेहमान आते हैं तो वे उनसे इसी में बात करते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले, हमारा परिवार आजीविका की तलाश में इस क्षेत्र से असम चला गया था। अब हम असमिया बन गए हैं।

असम एक लघु भारत है। उन्होंने कहा, मैं छत्तीसगढ़ी सहित आठ-नौ भाषाएं बोल सकता हूं। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराकर उसे 15 वर्ष के शासन से हटाया था। माना जाता है कि साहू समाज ने भी कांग्रेस का समर्थन किया था। राज्य में साहू समाज की आबादी लगभग 14 फीसदी है।

प्रमुख समाचार

एक साथ चुनाव कराने कोविंद की अध्यक्षता में पहली बैठक

नईदिल्ली। एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति ने शनिवार को अपनी पहली बैठक की। बैठक को

परिचयात्मक बताते हुए, विवरण से अवगत अधिकारियों ने कहा कि समिति को दिए गए जनादेश के बारे में रोडमैप पर चर्चा की गई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप और पूर्व सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी बैठक में मौजूद थे। शनिवार को पहली बैठक में इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए राजनीतिक दलों और विधि आयोग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि एक साथ चुनाव पैनल ने समकालिक चुनावों के मुद्दे पर विचार जानने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। पैनल सुझाव देने के लिए विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए।

अमरिंदर सिंह ने ट्रुडो को सौंपी थी आतंकियों की सूची

नईदिल्ली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी और वांछित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के बारे में कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन

ट्रुडो के निराधार आरोपों की कड़ी निंदा की है। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक राय लेख में सिंह ने कनाडा द्वारा भारत विरोधी तत्वों और आतंकवादियों को शरण देने के बारे में चिंता व्यक्त करने के भारत सरकार के पिछले प्रयासों पर प्रकाश डाला, और कनाडा पर आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को राजनीतिक शरण प्रदान करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2018 में एक बैठक के दौरान ट्रुडो को सौंपी गई ए-श्रेणी के आतंकवादियों की एक सूची का हवाला दिया, जिसे कनाडा ने कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने लिखा कि जब मैं फरवरी 2018 में अमृतसर में भारत सरकार की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में ट्रूडो से मिला, तो मैंने कार्रवाई के लिए उन्हें ए-श्रेणी के नौ आतंकवादियों की एक सूची सौंपी। लेकिन कनाडाई सरकार ने सूची को पूरी तरह से नजरअंदाज करना चुना।

दिल्ली विवि छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी ने लहराया परचम

नईदिल्ली। शनिवार शाम को संपन्न हुई वोटों की गिनती के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) में केंद्रीय पैनल के चार पदों में से तीन पर जीत हासिल की। एबीवीपी के तुषार डेढ़ा ने

अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, जबकि अपराजिता छात्र संघ के सचिव पद पर चुनी गईं। सचिन बैसला संयुक्त सचिव हैं। इस बीच, राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के उम्मीदवार अभि दहिया ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। शुक्रवार को छात्रसंघ का चुनाव हुआ। डूसू चुनाव में हमेशा एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर देखी गई है। चुनाव में चार पदों के लिए चौबीस उम्मीदवार मैदान में थे। केंद्रीय पैनल के लिए 52 कॉलेजों और विभागों में चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए गए, जबकि कॉलेज यूनियन चुनावों के लिए मतदान कागजी मतपत्र पर हुआ। विश्वविद्यालय में 42 प्रतिशत मतदान हुआ। डूसू चुनाव में करीब एक लाख छात्र वोट देने के पात्र थे। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने एबीवीपी उम्मीदवारों को एक्स पर बधाई दी।

फाइव आईज ने की भारत के खिलाफ ट्रुडो की मदद

नईदिल्ली। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी की मौत को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अमेरिका के एक सरकारी अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने पुष्टि की है कि फाइव आईज भागीदारों के बीच साझा खुफिया जानकारी थी, जिसके कारण कनाडाई प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रुडो ने कनाडाई धरती पर एक खालिस्तानी चरमपंथी की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता के बारे में आपत्तिजनक आरोप लगाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के 24 घंटे के ऑल-न्यूज नेटवर्क सीटीवी न्यूज चैनल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइव आईज पार्टनर्स के बीच साझा खुफिया जानकारी थी, जिसने भारत सरकार और एक कनाडाई नागरिक की हत्या के बीच संभावित लिंक के ट्रुडो के सार्वजनिक आरोप की जानकारी दी थी। फाइव आइज़ नेटवर्क एक खुफिया गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। यह निगरानी-आधारित और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों है।

विश्व बैंक ने पाकिस्तान को नीतियों में सुधार की दी चेतावनी

नईदिल्ली। विश्व बैंक ने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4 प्रतिशत हो गई है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण 12.5 मिलियन से अधिक लोग पीड़ित हैं। विश्व बैंक

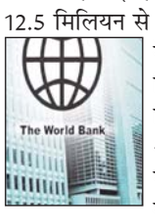

ने नकदी संकट से जूझ रहे देश से वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। ड्राफ्ट पॉलिसी नोट्स का अनावरण करते हुए वाशिंगटन स्थित ऋणदाता ने कहा कि पाकिस्तान में गरीबी एक वर्ष के भीतर 34.2 प्रतिशत से बढ़कर 39.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें 12.5 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। इसमें कहा गया है कि लगभग 95 मिलियन पाकिस्तानी अब गरीबी में रहते हैं। पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल अब गरीबी कम नहीं कर रहा है, और जीवन स्तर समकक्ष देशों से पीछे हो गया है।पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक के प्रमुख देश अर्थशास्त्री टोबियास हक ने कहा कि वैश्विक ऋणदाता ने पाकिस्तान से वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए अपनी कृषि और अचल संपत्ति पर कर लगाने और फिजूल खर्चों में कटौती करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी आग्रह किया।

कब गठित होगा 8वां वेतन आयोग

एक करोड़ सरकारी कर्मियों-पेंशनरों को 4 फीसदी मिलेगा डीए-डीआर

केंद्र सरकार में लगभग एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए वृद्धि की सौगात मिलेगी। राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में %ओपीएस% का मुद्दा रखने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार का कहना है कि इस बार कर्मियों का डीए 46 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा। ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता, जिसके चलते केंद्र सरकार, डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी न करे। कर्मचारी संगठनों को पूरी उम्मीद है कि सरकार, डीए की मौजूदा दर को 46 प्रतिशत पर ले जाएगी। इसके बाद जनवरी 2024 में जब चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ, महंगाई भत्ता 50त्न होगा तो केंद्र सरकार के समक्ष, दमदार तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। सम्भव है कि केंद्रीय कैबिनेट की आगामी बैठक में डीए बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी।

गत वर्ष मिला था डीए/डीआर

बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 28 सितंबर को डीए की दरों में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को दीवाली से पहले महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का तोहफा मिल गया था। वह भत्ता पहली जुलाई 2023 से जारी हुआ था। उस वक्त 34 प्रतिशत की दर से मिल रहा महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत हो गया था। उसके बाद जनवरी 2023 से उक्त भत्ते में दोबारा से चार फीसदी की वृद्धि हो गई। मौजूदा समय में

महंगाई भत्ता, 42 प्रतिशत की दर से मिल रहा है। अगर जुलाई 2023 से बढ़ने वाले भत्ते में भी चार प्रतिशत की वृद्धि होती है और जनवरी 2024 में भी इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज होती है तो उस वक्त डीए वृद्धि का ग्राफ पचास फीसदी हो जाएगा। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसा होता है तो बाकी के भत्ते भी स्वतः ही 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगे। वेतन का ढांचा भी बदल जाएगा।

दस साल का इंतजार जरुरी नहीं

सी. श्रीकुमार बताते हैं, संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार इस संदर्भ में विचार नहीं कर रही। ये सरकार की मनमर्जी ही तो है। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में %पे% रिवाइज हर दस साल में ही हो, यह जरुरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि पे कमीशन ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। कुछ माह बाद डीए 50 प्रतिशत के पार होने जा रहा है। ऐसे में नए डीए और एचआरए की संभावना बनना तय है। पिछला वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था। उसके तीन साल बाद आयोग की सिफारिशें लागू हुई। उस हिसाब से 2026 में वेतन रिवाइज होना चाहिए। इसके लिए 2023 में आयोग का गठन हो। संभव है कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग का गठन करे।

प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी

संसद में इस मुद्दे पर जो सवाल जवाब हुए हैं, उनमें कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच में कर्मियों के वेतन और पेंशन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में बताया था कि मुद्रा स्फीति के कारण वेतन और पेंशन के असली मूल्य में जो कटौती होती है, उसे पूरा करने के लिए डीए/डीआर दिया जाता है।

अब डीए 42 प्रतिशत हो गया है। प्रति व्यक्ति आय तीन गुणा हो गई। इसके साथ वस्तुओं के दाम भी उसी अनुरुप में बढ़े हैं। मतलब, केंद्र सरकार के कर्मी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पिछले तीन वेतन आयोगों की तरफ से कहा गया है कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए तो मुद्रा स्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाए। जनवरी 2024 में डीए 50 के पार हो जाएगा। अब सरकार कह रही है कि वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह, माओवादियों ने बुलाया बस्तर बंद, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

जगदलपुर। नक्सली हर साल की तरह इस साल भी पीएलजीए सप्ताह मना रहे हैं। 21 सितंबर से 27 सितंबर तक नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) ने स्थापना दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। जिसकी शुरुआत हो गई है। इस दौरान नक्सलियों ने बस्तर में बंद का आह्वान किया है। इस सप्ताह को सफल बनाने के लिए बस्तर संभाग के अंदरुनी इलाकों में पर्चे फेंके गए हैं। जिसमें नक्सलियों ने स्थापना दिवस को लेकर कई बड़ी बातों का ऐलान किया है।

इस दौरान सुकमा के इंजरम भेज्जी मार्ग पर नक्सलियों ने पर्चा फेंका है। जिसमें नक्सली संगठन की स्थापना दिवस की 19वीं वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया है। नक्सलियों की तरफ से की गई इस घोषणा के बाद बस्तर में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। ट्रेनों के ऑपरेशन को लेकर भी एहतियात बरते जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से विशाखापट्टनम किरंदुल में यात्री ट्रेनों के संचालन पर सतर्कता बरती जा रही है। ट्रेनों को किरंदुल नहीं भेजने का फैसला किया गया है। पीएलजीए सप्ताह के दौरान ट्रेनों के संचालन को लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है।

आईजी सुंदरराज पी ने कहा पीएलजीए सप्ताह के तहत नक्सलियों के बस्तर बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन को संचालित किया जा

रहा है। नक्सली हिंसा को रोकने की तैयारी की गई है। तेलंगना-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से तेलंगाना जाने वाली गाड़ियों को सुरक्षा के लिहाज से रोका जा रहा है। रात दस बजे के बाद इस इलाके से वाहन नहीं भेजने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस और तेलंगाना पुलिस दोनों राज्यों के बीच रात में चलने वाली गाड़ियों को लेकर बात भी कर रही है।

पीएलजीए सप्ताह के दौरान नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इससे पहले नक्सलियों ने तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर यात्री बसों को नुकसान पहुंचाया था। नक्सलियों की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां और छत्तीसगढ़ पुलिस मुस्तैद है। नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर खुफिया एजेंसिया भी अलर्ट हैं।

आईईडी ब्लास्ट में घायल हुआ डीआरजी जवान

बीजापुर। बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र के दुरधा के जंगल मे शुक्रवार को आईईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से डीआरजी जवान घायल हो गया। घटना के बाद तत्काल साथियों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती कराया। जवान की हालत को देखते हुए उसे मेकाज जगदलपुर रेफर किया गया। जहां जवान की हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को डीआरजी जवानों की टीम बीजापुर की टीम जांगला व नैमेड थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव कैका, दुरधा व मोसला की तरफ नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई थी। सर्चिंग से वापसी के दौरान दोपहर एक बजे के करीब दुरधा के जंगल में आईईडी ब्लास्ट होने से आरक्षक सन्नू हेमला 45 वर्ष इसकी चपेट में आकर घायल हो गया। घायल जवान सन्नू हेमला को बेहतर इलाज के लिए बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जवान की हालत को देखते हुए उसे मेकाज रेफर कर दिया गया। शुक्रवार की शाम करीब सात बजे जगदलपुर लाया गया, जहां से जवान को बेहतर उपचार के लिए एसआईसीयू में भर्ती किया गया। शनिवार की सुबह 8.49 बजे उसे मेकाज से एंबुलेंस के माध्यम से उसे एयर पोर्ट ले जाया गया।

रायगढ़ में डेंगू के खिलाफ अभियान सरकारी और प्राइवेट अस्पताल अलर्ट

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। प्रदेश के ज्यादा आबादी वाले शहर डेंगू की चपेट में हैं। रायगढ़ में भी डेंगू के मरीज लगातार मिल रहे हैं। रायगढ़ में डेंगू से अब तक 300 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से तीन लोगों की मौत हुई है। शहर में बढ़ रहे डेंगू को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम

मैदान में सर्वे करा रही है ताकि बीमारी ज्यादा ना फैले। सर्वे के दौरान ही टीमें लोगों को डेंगू से बचने के तरीके और मरीज में लक्षण दिखने पर डॉक्टरी टीम से कंसल्ट करने की अपील भी कर रही है।

डेंगू का लार्वा साफ और स्थिर पानी में पनपता है, इसलिए लोगों से अपने आसपास की सफाई करने की अपील की जा रही है। डॉक्टर्स ने शहर में सर्वे कर रही सभी टीमों को डेंगू की रोकथाम, जांच और इलाज की जानकारी दी है। किसी भी मरीज में डेंगू के लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर टेस्ट कराने की अपील की गई है।

रायगढ़ शहर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू सर्वे के लिए 180 मितानिन, 160 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 13 एएनएम और 42 सुपरवाइजर को डोर टू डोर सर्वे की जिम्मेदारी दी है। ये टीम लोगों को जागरुक भी कर रही है।

नगर निगम आयुक्त, सुनील चंद्रवंशी ने कहा नगर निगम की करीब 400 लोगों की टीम साफ सफाई में जुटी है। 24 टीम दवाओं का स्प्रे और पाउडर छिड़काव कर रही है। 8 टीमें फॉगिंग के लिए तैनात की गई हैं।

रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने मरीजों की जांच और उपचार को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल में डेंगू के लिए एक आइसोलेटेड वॉर्ड तैयार किया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज और शहर के निजी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है।

डेयरी संचालन से समूह की महिलाएं बनी सक्षम उद्यमी

समूह की 70 महिलाओं को मिला रोजगार

बलरामपुर। दूरस्थ क्षेत्रों के महिलाएं, पशुपालक आज आजीविका से जुड़कर सशक्त हो रही है। उन्हें गांव में ही रोजगार मिलने से महिलाओं ने खुशी जाहिर की। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर और राजपुर में स्व सहायता समूह की महिलाएं डेयरी व्यवसाय से जुड़कर दूध उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इसका सीधा लाभ आस पास के सभी पशुपालकों को हो रहा है।

रीपा के तहत दूध इकाई स्थापित होने से महिला उघमिता को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में दो समूह में महिलाएं मिलकर दूधवाला नाम से डेयरी संचालन कर रही है। महिलाओं ने बताया कि गांव के आस पास के पशुपालकों से दूध खरीदकर दूध तथा दूध से निर्मित खाघ पदार्थों का विक्रय कर रही हैं। महिलाओं और पशुपालकों को बाजार मिलने से उनकी आय मे वृद्धि हो रही है।

योजना के शुरुआती चरण में वाड्रफनगर और राजपुर में दूध संग्रहण केंद्र खोले गए है, जिसमें विभिन्न समूह की 70 महिलाएं दूध संग्रहण और वितरण का कार्य कर रही हैं। समूह की महिलाओं के द्वारा आस-पास के 10 गावों के 76 पशुपालकों से लगभग 152 लीटर दूध की खरीदी नियमित रूप से की जा रही है। समूह की महिलाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र के 136 उपभोक्ताओं को प्रतिदिन बिहान मार्ट के द्वारा दूध का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही बचे हुए दूध से समूह की महिलाएं विभिन्न प्रकार के मिठाईयां तैयार कर रहीं हैं। इस योजना की शुरुआत से अब तक दोनों केंद्रों के द्वारा लगभग 05 लाख 70 हजार की दूध की खरीदी की गई है, तथा 05 लाख 64 हजार की बिक्री की जा चुकी है। साथ ही बचे हुए दूध से मिठाइयों का निर्माण कर उन्हें बेचकर अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। सदाबहार समूह की सदस्य श्रीमती मीना बताती है कि महिलाओं को मिलाकर एक उत्पादक समूह का गठन किया गया है, जिसका सदाबहार उत्पादक समूह रखा गया है।

बीएसपी लूट कांड में बड़ा खुलासा, गार्ड को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम

भिलाई। बीएसपी के पीसीबी प्लांट में 5 आरोपियों ने घुसकर गार्ड को बंधक बनाया और लाखों रुपये का तांबा लेकर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस दौरान पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

बीएसपी के पीसीबी प्लांट में तांबा का प्रोडक्शन होता है। 18 सितंबर की रात पीसीबी प्लांट में देर रात पांच आरोपी घुसे। चोरी की नीयत से घुसे युवक अपने साथ लोहे की रॉड लेकर आए थे। जिस समय आरोपी प्लांट में घुसे उस समय 5 गार्ड ड्यूटी पर थे। गार्ड ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक मुंह में स्कार्फ बांधकर घुसे थे। उन्होंने सुरक्षा गार्ड की बंदूक छीनी और उन्हें धमकाया।

इसके बाद उन्होंने प्लांट के दरवाजे का कांच तोड़ा और उसके अंदर घुसकर लाखों रुपये का तांबा निकालने लगे। आरोपियों की पूरी करतूत सीसीटीवी में में कैद हो गई है। जिसके आधार पर पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। भिलाई 3 टीआई मनीष शर्मा ने बताया कि घटना की शिकायत चुनकट्टा सेलुद निवासी गार्ड देवदास कोसले ने की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

रायगढ़ प्राइवेट बैंक लूट मामले में पुलिस का सीन रीक्रिएशन, आरोपियों को लेकर बैंक पहुंची पुलिस

रायगढ़। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के मामले में रायगढ़ पुलिस एक बार फिर प्राइवेट बैंक पहुंची। रायगढ़ के एसएसपी सदानंद कुमार, एसडीओपी दीपक मिश्रा और पुलिस के आला अधिकारी बैंक पहुंचे। बैंक के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बैंक खुलने के बाद सभी बैंक कर्मचारियों को बैंक के बाहर खड़ा करवाया गया है। पुलिस बैंक के अंदर पहुंची। खास बात थी कि इस बार पुलिस आरोपियो को भी अपने साथ लेकर आई। बैंक डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस ने पूरा क्राइम सीन रीक्रियट किया। सुबह 9 बजे पुलिस पकड़े गए 5 आरोपियों को लेकर बैंक पहुंची। लगभग दो घंटे पुलिस और आरोपी बैंक में मौजूद रहे। 19 सितंबर को बैंक रॉबरी की घटना फिर से दोहराई गई। इसके बाद कड़ी सुरक्षा केबीच आरोपियों को ले जाया गया। बैंक रॉबरी के मामले में पुलिस ने बताया कि घटना में 10 आरोपी थे। जिनमें से 5 पुलिस की गिरफ्त में है जबकि पांच अभी भी फरार है।

रायगढ़ शहर में मंगलवार 19 सितंबर को हर रोज की तरह प्राइवेट बैंक खुला। बैंक खुलने के बाद बैंक स्टाफ के साथ ही कई आम लोग भी बैंक के अंदर पहुंचे। लेकिन कुछ ही देर में ऐसा कुछ हुआ जिसे अब तक बैंक में मौजूद लोगों ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। बैंक में पहुंचा एक आदमी मैनेजर के कैबिन में पहुंचा और हथियार निकालकर उसे

धमकाते हुए बैंक में मौजूद रुपये निकालने को कहा। इस बीच कैबिन के बाहर मौजूद और 4 लोगों ने बैंक स्टाफ और वहां मौजूद कुछ और लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। बैंक मैनेजर ने जब रुपये देने से मना किया तो बदमाश ने उनकी जांघ में चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद घंटे भर के अंदर बदमाश 5 करोड़ 62 लाख रुपये कैश और गोल्ड लेकर फरार हो गए। बैंक से करोड़ों की लूट की घटना आग तक फैली। पुलिस मौके पर पहुंची। रायगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बैंक रॉबरी के तीन आरोपियों को रामानुजगंज के छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर पकड़ा। चैकपोस्ट पर तलाशी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा। जिसमें तीन आरोपी मौजूद थे। ट्रक में ही बैंक लूट के करोड़ों रुपये और सोने के ज्वेलरी के पैकेट्स थे। तीन आरोपियों की निशानदेही पर दो और आरोपी पकड़ाए। जो ट्रक के आगे कार से बॉर्डर पार कर झारखंड जाने की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कैश 4 करोड़ 19 लाख रुपये और 78 पैकेट सोना जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपये थी बरामद किया। लूट की कुल रकम 5 करोड़ 62 लाख रुपये है। आरोपियों के पास से पुलिस ने देसी राइफल, 1 कट्टा, 8 कारतूस, क्रेटा गाड़ी, ट्रक जब्त किया।

बैंक रॉबरी के आरोपी बिहार के शेरघाटी गैंग के सदस्य है। जो पहले भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। **आरोपियों के नाम**-राकेश कुमार गुप्ता उम्र 22 साल, निवासी बार थाना शेरघाटी, जिला गया, बिहार। उपेंद्र सिंह उम्र 50 साल, निवासी गुरुवा, जिला गया, बिहार। निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास उम्र 32 साल, निवासी खरसरी थाना मधुबन, जिला धनबाद, बिहार। राहुल कुमार सिंह, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम डोभी, थाना डोभी, जिला गया, बिहार। अमरजीत कुमार, उम्र 24 साल, निवासी भरारी थाना, शेरघाटी, जिला गया, बिहार।

सीएम भूपेश ने रायगढ़ पुलिस की पीठ थपथपाई- छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों रुपये के बैंक लूट का जल्द खुलासा करने पर रायगढ़ पुलिस टीम को बधाई दी थी। सीएम ने ट्वीट कर कहा- बधाई छत्तीसगढ़ पुलिस! यह नवा छत्तीसगढ़ है, चोर, लुटेरे, डकैत कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। यहां कानून का राज ही रहेगा। चाहे बैंक लूटने वाले हो या फिर छत्तीसगढ़ लूटकर पनामा की बैंक भरने वाले सबका हिसाब होगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोरबा की कल्पना मेहता बनीं नेशनल प्लेयर

कोरबा। कोरबा की बेटी कल्पना रोलबॉल के राष्ट्रीय टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ टीम का हिस्सा बनी हैं। कल्पना स्कूल के समय से ही रोल बॉल खेलती आ रही है। उन्होंने स्कूल में भी कई मेडल जीते हैं। अब नेशनल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनकर कल्पना ने जिले का नाम रोशन किया है। दरअसल, जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में रहने वाली कल्पना वैसे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। लेकिन उनका दिल रोल बॉल के लिए धड़कता है। कल्पना ने स्कूल में रहते रोल बॉल खेलना शुरू किया था। स्कूल में उन्होंने कई मेडल जीते और राष्ट्रीय स्पर्धा में शिरकत की। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कल्पना का परिवार इतना सक्षम नहीं था कि इस महंगे खेल में कल्पना का सपोर्ट कर पाता।यही कारण है कि कल्पना ने बीच में खेलना बंद कर दिया। हालांकि फिर इसी खेल में कल्पना ने मुकाम हासिल करने की जिद्द पकड़ ली। कुछ दिनों पहले जब इस खेल के ओपन ट्रायल्स दुर्ग में आयोजित हुए। तब कल्पना का चयन छत्तीसगढ़ की टीम में किया गया।

अवैध ई-टिकट बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार

जशपुर। पत्थलगांव शहर में गलत तरीके से ई-टिकट बनाने वाले पर रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) अम्बिकापुर टीम ने दबिश दी। टीम ने दबिश देकर 69 ई-टिकट जब्त किए। इसकी कीमत डेढ़ लाख से अधिक बताई जा रही है। संचालक पर्सनल आईडी पर ई-टिकट बनाकर बेच रहे थे। संचालक के खिलाफ रेलवे एक्ट की कार्रवाई की गई है। अम्बिकापुर आरपीएफ कर्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पत्थलगांव शहर के अम्बिकापुर रोड स्थित बंटी फोटो कॉपी दुकान में गलत तरीके से ई-टिकट बनाया जा रहा था। टीम ने दुकान में दबिश दी। यहां पर्सनल आईडी पर टिकट बनाकर ई-टिकट का व्यापार किया जा रहा था। दुकान से 69 टिकट बरामद की गई जिसकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने सीपीयू व मोबाइल भी जब्त किया है। आरपीएफ ने रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संचालक पुरुषोत्तम अग्रवाल को अंबिकापुर रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जहां से अर्थदंड लगाकर जमानत पर छोड़ा गया।

बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, नदी-नाले उफान पर

बेमेतरा। बेमेतरा जिले में फिर से बारिश शुरू हो गई है। बीते एक हफ्ते पहले जिले में हुई बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के हालात थे, अब फिर से ऐसे ही हालात बन रहे है। बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस मानसून पूरे जिले में औसतन 882.4 मिमी बारिश हो चुकी है। कृषि प्रधान जिला बेमेतरा में लगातार बारिश होने से धान के खेत में पानी भर गया। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले के नवकेशा नाला में बारिश का पानी पुल के ऊपर चढ़ गया है, बावजूद क्षेत्र के लोग जान-जोखिम में डालकर आवागमन करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षागत दृष्टिकोण से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इसके अलावा जिले के शिवनाथ, सकरी, फोक नदी समेत डोठू नाला के किनारे बसे गांव के लोग बारिश के चलते अब परेशान हैं। क्योंकि, इन इलाकों में बीते दिनों बाढ़ का पानी घुस गया था, जिसके कारण प्रशासन को इन लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया था।

विधानसभा में निर्वाचन व्यय की सीमा 28 लाख से बढ़कर हुई 40 लाख रूपए

कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों एवं विधानसभा आम निर्वाचन के कार्यों एवं दायित्वों से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के प्राप्त आदेश एवं दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। बैठक में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में, मतदान केन्द्र का भवन परिवर्तन, स्थल परिवर्तन और नाम परिवर्तन, आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्ययों का मानक दर निर्धारण और चुनाव संचालन (संशोधन) नियम 2022 चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 90 का संशोधन चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि के संबंध में आवश्यक चर्चा हुई।

चला संगी वोट देहे जाबो मानव श्रृंखला बनाकर किया मतदाता जागरूक

मनेन्द्रगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को मताधिकार के महत्व को बताने, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा की उपस्थिति में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन अकादमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल तेन्दूडांड झगराखाड़ मनेन्द्रगढ़ में किया गया। कार्यक्रम में अकादमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल तेन्दूडांड के सैकड़ों बच्चों ने भाग लेकर चला संगी वोट देहे जाबों मानव श्रृंखला बनाकर एवं मतदाता जागरूकता के नारे लगाकर शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया। स्कूल के बच्चों को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने कहा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार एवं शत प्रतिशत मतदान का बहुत ही महत्व है। हम सबको मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से अपने परिवार के साथ-साथ सभी नगरवासियों को मतदान के लिए प्रेरित करना है, मताधिकार एवं मत की वैल्यू को बताना है।

सामुदायिक सहभागिता से बदली प्राथमिक शाला मुंधा की तस्वीर

महासमुन्द। शासकीय प्राथमिक शाला मुंधा विकासखंड सरायपाली के शिक्षकों द्वारा बच्चों के अधिगम स्तर को सुधारने कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा बच्चों की पढ़ाई स्तर सुधारने जो प्रयास किये जा रहे है ,उसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला मुंधा के प्रधान पाठक श्रीमती शीला विश्वास एवं ?शिक्षकों के ऐसे ही नवाचार और पहल से यहां के शिक्षा स्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरायपाली के उत्तर में 14 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेशीय गांव मुंधा है। जहां के लोग कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर है।

प्रधान पाठक श्रीमती शीला विश्वास बताती हैं - मैं जब प्राथमिक शाला मुंधा मे आई परिस्थितिया विपरीत थी और ऐसी परिस्थिति में कार्य करना आसान नही था लेकिन बस मैने मन में ठान लिया था इस

अंधेरे से खुद अकेले नहीं निकलना है बल्कि अपने बच्चो के साथ अंधेरो को चीरते आगे बढना है फिर चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यो न हो।

विद्यालय सक्रियता या उसकी सुरक्षा की बात हो तो बिना विद्यालय प्रबंधन समिति को सक्रिय किए बिना हम यह नही कर सकते। इसलिए सर्व प्रथम मैने विद्यालय प्रबंधन समिति को सक्रिय किया साथ ही साथ विद्यालय, परिवार और समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित किया। शाला में कक्षा-कक्ष साधारण थे और शाला मे कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं होती थी। जिससे बच्चो को पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। तभी यहां के शिक्षकों द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बीआरसीसी सतीश स्वरूप पटेल के मार्गदर्शन एवं संकुल समन्वयक पुरूषोत्तम पटेल के निर्देशन में कुछ नवाचार किये गए जैसे- विद्यालय संचालन हेतु नवाचार मे प्रार्थना सत्र मे प्रतिदिन अलग - अलग बच्चो द्वारा प्रार्थना संचालन माईसेल्फ इन्ट्रोडक्शन, सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी की जानकारी विशेष दिनों की जानकारी, प्रमुख समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण समाचार वाचन करना, विषय को रुचिकर बनाने पाठ्यक्रम की आवश्यकता अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कर विद्यार्थीयो को प्रोत्साहित किया गया तथा गतिविधि आधारित शिक्षण प्रारंभ किया हमारे स्कूल मे बाल केबिनेट गठन और एसएमसी के सदस्यो को क्रियाशील कर माता उन्मुखीकरण (अंगना म शिक्षा) कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका समुचित प्रभाव देखने को मिलने लगा।

प्रधान पाठक के नेतृत्व में यहां के शिक्षकों द्वारा प्रत्येक शनिवार सुरक्षित शनिवार और बाल सभा का आयोजन किया जाता है जिसमे लेखन, गायन, पेपर क्राफट, चित्रकला, योगाभ्यास भी करवाया जाता है। स्वयं प्रधान पाठक शीला विश्वास के द्वारा स्कूल में वाल पेंटिंग किया गया ताकि बच्चो को प्रिंट रिच वातावरण मिल सके और चित्रकला के प्रति उनकी रुचि जागृत हो और चित्रकला के प्रति उनकी रुचि जागृत हो। प्रतिदिन स्कूल में पढ़ाई , मुस्कान पुस्तकालय, टीएलएम कार्नर, खिलौना कार्नर, जन्मदिन, बोर्ड, स्टार आफ

कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की दृष्टि से कृषि उपज मंडी बोर्ड का किया निरीक्षण

बेमेतरा। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने आज आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की सिलसिले में कृषि उपज मंडी परिसर का अवलोकन किया। कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की दृष्टि से आवश्यक सभी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए लोकनिर्माण विभाग एवं कृषि उपज मंडी सचिव को निर्देशित किया है।

कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कृषि उपज मंडी परिसर से ही विधानसभा निर्वाचन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी परिसर में होती है। इसलिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण तैयारी शीघ्रता से पूरा करे। विधानसभा क्षेत्रों में मतदान दल समाग्री का वितरण,मतदान दल की रवानगी, दोनो विधानसभा क्षेत्र का स्ट्रांगरूम, मतगणना रूम, एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त आब्जर्वर का मॉनिटरिंग कक्ष, जिला निर्वाचन अधिकारी का

मॉनिटरिंग कक्ष, सीसीटीवी रूम, सुरक्षा अधिकारियों का कक्ष एवं कानून तथा सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा जवानों के ठहरने की पूरी व्यवस्था इसी नवीन कृषि उपज मंडी परिसर किया जाता है। कलेक्टर ने विधानसभावार मतपेटी वितरण एवं मतगणना के दौरान लगने वाले सावधानियों के बारे में चर्चा कर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान अन्य स्टाफ भी उपस्थित थे ।

कांग्रेस जो भ्रष्टाचार करती है उसकी करतूतें झारखंड तक सुनते है : अन्नपूर्णा

छत्तीसगढ़ का डंका पूरे देश में बजवाना है तो भाजपा को वोट दें: कृष्णपाल, भाजपा की सरकार बनाने से आपको डबल फायदा होगा: भानुप्रताप

गरियाबंद। मैनपुर में परिवर्तन यात्रा की आमसभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार के मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने कहा कांग्रेस राज मे छत्तीसगढ़ बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध ने नंबर वन 1, वादाखिलाफी में नंबर 1 है मोदी जी का भेजा अन्न भी कांग्रेसी खा गए इंसान तो इंसान गाय के गोबर का पैसा भी खा गए। ऐसी सरकार को छत्तीसगढ़ के हित के लिए हटाना ही होगा। कांग्रेस राज ने हम सब कुछ दूसरे देशों से मंगवाते थे आज मोदी राज में हम दूसरे देशों को सामान बेचते है। मोदी जी न होते तो 370 धारा नही हट सकती थी,राम मंदिर नही बनता, देश का विकास न होता ।मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार विकास के नए कीर्तिमान बनाएगी और अगर छत्तीसगढ़ का डंका पूरे देश में बजवाना है तो भाजपा को वोट दे।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कांग्रेस यहां जो भ्रष्टाचार करती है उसकी बाते हम झारखंड तक सुनते है नारी उत्पीडन् यहां चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार नारियों का शोषण कर रही है वही भाजपा की मोदी सरकार नारियों का वंदन कर रही है वर्षों से अटका महिला आरक्षण का नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी सरकार ने पास करा महिलाओं को राजनीति में उनका हक देने का एक उपहार देने का काम किया। मोदी जी महिलाओं के उत्थान के किए लगातार काम कर रहे है उनके नेतृत्व में आने से महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव हो रहा है वह महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रहे है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा देश की शिक्षा नीति में मोदी जी ने बड़ा बदलाव किया हर प्रदेश की रक्षा प्रणाली में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर प्रदेश का गौरव बढ़े उनकी संस्कृति विश्व पटल पर कीर्तिमान रचे यह कार्य मोदी जी कर रहे है।कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी इसीलिए ऐसी सरकार को हटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। केंद्रीय राज्य मंत्री भानुप्रताप वर्मा ने कहा 2003 में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद 15 साल तक भाजपा को अवसर दिया था इस बार भी आप ऐसे ही करेंगे हमे विश्वास है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कांग्रेस सरकार जनता तक पहुंचने नही दे रही है भाजपा की सरकार अगर प्रदेश में बनेगी तो केंद्र की योजनाओं का लाभ भी आपको मिलेगा प्रदेश की भाजपा सरकार भी आपके लिए कई काम करेगी आपको डबल फायदा होगा। वर्मा ने कहा कांग्रेस सरकार ने सभी पर कर्ज चढा दिया है हर व्यक्ति पर 40 हजार रु का कर्जा है कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने भी यही किया था 2008 से 2014 तक मात्र 6 साल में 18 लाख करोड़ के कर्ज को 52 लाख करोड़ कर दिया लोगो को खूब लोन बाटा बैंको को भी खाली कर दिया था कांग्रेस की सरकार केवल खजाने खाली करने का काम करती है। आम सभा में प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव, केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री कृष्ण कुमार गुर्जर,श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा,श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यात्रा प्रभारी शिवरतन शर्मा,सांसद चुन्नीलाल साहू,पुर्व सांसद चंदुलाल साहू,श्रीमती पिंकी शिवराज शाह,क्षेत्रीय विधायक डमरुधर पुजारी,पुर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी, जिलाध्यक्ष राजेश साहू, विधानसभा प्रभारी महेंद्र पंडित, भागीरथी मांझी, हलमन सिंह ध्रुवा, बोधनराम नायक, योगेश शर्मा, कुंजबिहारी बेहरा, पुनीत राम सिन्हा, केनुराम यादव, जनपद अध्यक्ष नुरमति मांझी, मंडल अध्यक्ष गुरुनारायण तिवारी, दुलार सिन्हा, सीताराम यादव, लुद्रास साहू, चंद्रशेखर साहू, राजेंद्र गोलछा, दिलीप साहू, मनोहर बघेल,महेश कश्यप सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता गण माजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

हर विधानसभा क्षेत्र में दो अक्टूबर को भरोसा यात्रा निकालेगी कांग्रेस

रायपुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शुक्रवार को छह कमेटियों की मैराथन बैठक हुई। करीब आठ घंटे तक चली बैठक में तय किया गया कि सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में दो अक्टूबर को भरोसा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें सभी बड़े स्थानीय नेता अपने-अपने क्षेत्र में शामिल होंगे। इसके लिए विधानसभावार जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का छत्तीसगढ़ दौरा भी प्रस्तावित किया गया है। राहुल 25 सितंबर को बिलासपुर के तखतपुर में चुनावी सभा करेंगे। इस दौरान वे सीएम आवास योजना के तहत सात लाख आवासों से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को प्रमाणपत्र सौंपेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने एक हजार करोड़ का बजट आवंटित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा 28 सितंबर को बलौदाबाजार में प्रस्तावित है। प्रियंका गांधी चार अक्टूबर को कांकेर में आयोजित पंचायती राज नगरीय निकाय सम्मेलन में शामिल होंगी। इस दिन कांकेर मेडिकल कालेज का भूमिपूजन भी किया जाएगा।

सीएम ने छत्तीसगढ़ की सहकारिता नई राहें-नए कीर्तिमान स्मारिका का विमोचन किया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यहाँ

अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) की स्मारिका छत्तीसगढ़ की सहकारिता- नई राहें-नये कीर्तिमान का विमोचन किया । स्मारिका में राज्य सरकार की वर्ष 2019 से 2023 तक विगत पांच वर्षों के कार्यकाल में सहकारिता के क्षेत्र में अर्जित की गयी विशिष्ट उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है । मुख्यमंत्री ने बैंक के पदाधिकारियों को बधाई एवँ शुभकामनाएं दी । इस अवसर पर छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चन्द्राकर, संचालक श्री द्वारिका साहू, श्री राकेश सिंह ठाकुर, प्रबन्ध संचालक श्री के.एन. कान्डे, डीजीएम श्री भूपेश चन्द्रवंशी, प्रबंधक श्री अभिषेक तिवारी और लेखाधिकारी श्री प्रभाकर कांत यादव भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से बिलासपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सदस्यों ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से यहाँ उनके निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में बिलासपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने सदस्यों को बधाई एवँ शुभकामनाएं दी तथा आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री इरशाद अली, उपाध्यक्ष श्री संजीव पाण्डेय, सचिव श्री दिलीप यादव, कोषाध्यक्ष श्री प्रतीक वासनिक, सह सचिव श्री दिलीप जगवानी तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री गोपीनाथ डे भी उपस्थित थे।

महाभारत सीरियल के श्रीकृष्णा नितीश भारद्वाज 25 को आ रहे छत्तीसगढ़

रायपुर। रायपुर संस्कार भारती छत्तीसगढ़

कला के द्वारा हमारी संस्कृति हमारी पहचान कार्यक्रम का आयोजन 25 सितंबर को गांधी मैदान रामानुजगंज में किया गया है। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता एवं महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण की मुख्य भूमिका में रहे नितीश भारद्वाज मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्य आकर्षण का केंद्र 1001 देव रूपों में सुसज्जित बालक- बालिकाओं की प्रस्तुति होगी। छत्तीसगढ़ प्रांत सह महामंत्री डॉ. पुरुषोत्तम चंद्राकर ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम, विशिष्ट अतिथि निरंजन पंडा जी (भोपाल) राष्ट्रीय विद्या सहसंयोजक एवं श्री अनिल जोशी (रीवा) मध्यमध्य क्षेत्र प्रमुख संस्कार भारती होंगे। श्री नीरज श्रीधर संस्कार भारती झारखंड प्रांत मंत्री, रंजीत सारथी जिला अध्यक्ष संस्कार भारती सरगुजा, अध्यक्षता रिखी क्षत्रीय छत्तीसगढ़ प्रांतीय अध्यक्ष संस्कार भारती के आतिथ्य में संपन्न होगा।

21 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत आज से

रायपुर। 21 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत रविवार से होने जा रहा है, जिसका समापन 15 अक्टूबर को होगा। अग्रवाल सभा रायपुर के द्वारा 19 मोहल्ला समितियों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में मोहल्ला समितियों के स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम एवं स्पर्धा आयोजित किया जाएगा। जयंती प्रभारी मनीष अग्रवाल व प्रचार प्रसार प्रमुख आयुष मुरारका ने बताया कि द्वितीय चरण में इन सभी मोहल्ला समितियों में प्रथम स्थान अर्जित करने वाले अग्रबन्धु सेंट्रल लेवल पर 10 से 15 अक्टूबर को अग्रसेन धाम छोकरा नाला में कार्यक्रम एवं स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को उद्घाटन समारोह में मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 25 सितंबर से

रायपुर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ब्लॉक स्तर में बच्चों से लेकर बुजुर्गो तक अपनी प्रतिभा दिखाई। इसके बाद स्लेक्टेड खिलाड़ी जिला स्तरीय खेल में शामिल हुए। इसी क्रम में राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक होगा। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जिला से चयनित खिलाड़ियों को शामिल होने के लिए संबधित जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन के संबंध में 24 सितंबर शाम 7 बजे सभी जिलों के दल मैनेजर और खेल अधिकारियों की बैठक सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है।

बैठक में विधावार प्रतिभागी, मैनेजरों की सूची के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। जिला कलेक्टर्स से कहा गया है कि जिले से आने वाले प्रतिभागियों के दल में शामिल दल प्रभारी और उनके सहयोगी स्टॉफ, प्रतिभागियों (पुरूष और महिला), वाहन चालक, परिचालक एवं वाहन की जानकारी 22 सितंबर को शाम 5 बजे तक ई-मेल आईडी dir-sportsyw.cg@gov.in पर भेजें क्योंकि आने-जाने और खाने-पीने के सभी खर्च को जिला कलेक्टर देंगे। राज्य स्तर पर आने वाले प्रतिभागी दलों के साथ संबंधित एक-एक डिप्टी कलेक्टर और उप पुलिस अधीक्षक की ड्यूटी लगाई जाए। महिला प्रतिभागियों के लिए महिला कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। प्रतिभागी को पहचान पत्र दिए जायेंगे। इसे पहचान पत्र के साथ ही यात्रा करना है। जिले के दल 24 सितंबर को शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दें। जिलों के दल मैनेजर प्रत्येक विधावार नियुक्त प्रभारी से समन्वय कर, प्रतिभागी, दल को सुव्यवस्थित रूप से प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं प्रतियोगिता आयोजन स्थल पर समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

एनएसयूआई सोशल मीडिया के पुनेश्वर बने प्रदेश उपाध्यक्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय पार्टी का दौरा जारी है। बैठके जारी है। पार्टी के पदों पर फेरबदल जारी है। कांग्रेस पार्टी पदों का चुनाव करते हुए नए-नए चेहरे को मौका दे रही है। इसी क्रम में पार्टी की स्टूडेंट्स विंग एनएसयूआई प्रदेशभर में काफी सक्रियता से काम कर रही है। चुवानी मौहोल पर एनएसयूआई सक्रिय है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं। इस बार प्रदेश एनएसयूआई के पदों का फेरबदल हुआ है। इस दौरान नए-नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है। इसी क्रम में छात्र नेता पुनेश्वर लहरे को एनएसयूआई सोशल मीडिया का नए प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पिछले पांच सालों से कांग्रेस छात्र नेता के रूप में काम किया है। कई आंदोलन और धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।

महाविद्यालय में प्रवेश का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के साथ-साथ कौशल का विकास करना है: कुलपति

रायपुर। गुरुकुल महिला महाविद्यालय कालीबाड़ी में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल ने कहा कि विदेशों की अपेक्षा भारत में महिला की गुणवत्ता एवं शक्ति अधिक है परंतु इसका उपयोग उनकी अपेक्षाकृत कम होता है। महाविद्यालय में प्रवेश का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के साथ-साथ कौशल का विकास करना है।

प्राचार्य डॉ. गुप्ता ने इंडक्शन का अर्थ बताते हुए छात्राओं को कहा कि महाविद्यालय में रहते हुए सभी शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से खुद को तराशने का प्रयास करना है और अपने भविष्य को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। कुलपति शुक्ला ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंडक्शन कार्यक्रम का हिन्दी अर्थ दीक्षारंभ कार्यक्रम होता है जोकि महाविद्यालय का प्रथम सोपान होता है तथा इसका अंतिम सोपान दीक्षांत समारोह के रुप में आयोजित किया जाता है। महाविद्यालय में प्रवेश का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के साथ-साथ कौशल का विकास करना है। विद्यार्थियों में जो गुणवत्ता होती है उसें सतह पर लाकर शिक्षको या प्राध्यापकों द्वारा पॉलिश किया जाता है। गुरुकुल की परंम्परा को बताते हुए उन्होने कहा कि यहाँ सभी विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को तराशा जाता है तथा समाज में कार्य करने के लिए उन्हें सौप दिया

जाता है। उन्होनें महिला शक्ति की महत्ता को बताते हुए कहा कि विदेशों की अपेक्षा भारत में महिला की गुणवत्ता एवं शक्ति अधिक है परंतु इसका उपयोग उनकी अपेक्षाकृत कम होता है। अतः उनके आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाना होगा ताकि हर क्षेत्र में वे आगे बढ़कर काम करें। इसी तरह हमारी भारतीय संस्कृति का परचम दूसरे देशों में फैलाना होगा। अध्यक्ष अजय तिवारी ने छात्राओं की उज्जवल भविष्य करने की कामना करते हुए महाविद्यालय में आचरण संहिता के पालन की अनिवार्यता को बताया। सचिव श्रीमती शोभा खंडेलवाल ने महाविद्यालय की ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. सीमा चन्द्राकर ने किया। इस अवसर पर नवप्रवेशित छात्रायें, महाविद्यालय के प्राध्यापक, अशैक्षणिक स्टॉफ उपस्थित थे।

वन नेशन वन इलेक्शन, संसद के विशेष सत्र, धान खरीदी पर बघेल ने फिर बोला केंद्र पर हमला

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा देश में जोर शोर से छाया हुआ था। इसी चर्चा के मद्देनजर कांग्रेस ने अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। बघेल ने कहा संसद के विशेष सत्र में इसके लाने की संभावना थी लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला बिल आया।

केंद्र में नई सरकार कराएगी जनगणना- सीएम बघेल ने महिला आरक्षण बिल पर भी मोदी सरकार को घेरा। सीएम ने कहा जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है वो साल 2039 में भी लागू होगा ये भरोसा नहीं है। क्योंकि पहले जनगणना होगी, फिर कमेटी बनेगी, उसके बाद होगा। अभी तो जनगणना ही शुरू नहीं हुई है। अभी विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव उसके बाद फिर जनगणना होगी, जो नई सरकार आएगी वह जनगणना कराएगी।

महंगाई से महिलाओं का ध्यान भटकाने लाया महिला आरक्षण बिल- भूपेश ने कहा आज महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, बेरोजगारी से पूरा देश त्रस्त है, खासकर महिला वर्ग जो महंगाई से त्रस्त है। उनका ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से बिल लाया गया है। इस बिल को 2024 में लागू किया जा सकता था। 2010 में जो बिल

पारित हुआ है यदि उस बिल को उठाकर लाते हैं तो वह 2024 में लागू कर सकते थे लेकिन महिला आरक्षण बिल लागू करने की नीयत इनकी नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान भटकने के लिए इस प्रकार से बिल आए हैं।

धान खरीदी पर मोदी को घेरा- सीएम ने धान खरीदी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा धान केंद्र सरकार खरीदती है तो उत्तर प्रदेश में धान 1200 रुपये में बेचने के लिए किसान क्यों मजबूर है। भूपेश बघेल ने कहा रमन सरकार धान का 300 रुपये बोनस दे रही थी जिसे बाद में बंद कर दिया गया। 15 क्विंटल धान खरीदने वाली सरकार ने क्या मोदी के कहने पर 10 क्विंटल कर दिया था। मोदी सरकार किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है लेकन कोई गुमराह होने वाला नहीं है।

कांग्रेस में प्रक्रिया के तहत टिकट बंटवारा- सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के उन आरोपों पर पलटवार किया जिसमें भाजपा ने कांग्रेस में विवाद के कारण टिकट फाइनल में देरी की बात कही थी। सीएम भूपेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने जाते हैं, इसका पता नहीं चलता। कांग्रेस में टिकट देने से पहले ब्लॉक के सजेशन जिले के सजेशन को लेकर जितने भी आवेदन आते हैं उस पर विचार किया जाता है।। प्रदेश इलेक्शन कमीशन इस पर चर्चा करती है। उसके बाद स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद सीईसी में फाइनल होता है। यह कांग्रेस की प्रक्रिया है।

25 को राहुल गांधी, 28 को खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा- भूपेश बघेल ने बताया कि 25 सितंबर को बिलासपुर में राहुल गांधी आएंगे। जिसमें साढ़े 7 लाख आवास योजना की राशि हितग्राहियों को बांटी जाएगी। बिलासपुर में राहुल गांधी एक बड़ी सभा भी करेंगे। 28 सितंबर को खड़गे बलौदाबाजार में भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और बेरोजगारी भत्ता हितग्राहियों को बांटा जाएगा। बघेल ने कहा कि आने वाले 4 अक्टूबर को प्रियंका गांधी फिर छत्तीसगढ़ आ सकती है। इस बार उनका दौरा कांकेर में होगा। कांकेर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, इंदिरा गांधी के नाम से दूसरा पंचायती राज और नगरी निकाय के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है।

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। सोसाईटी ऑफ एनर्जी इजीनियर्स एण्ड मैनेजर्स-सीम द्वारा 21 सितम्बर को

आयोजित 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड समारोह में यह सम्मान दिया गया। श्री आलोक कटियार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा उक्त पुरस्कार को डॉ. अशोक कुमार, उप महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरों, (बी.ई.ई.) भारत सरकार के उपस्थिति में प्राप्त किया गया। इस समारोह में क्रेडा की ओर से श्री संजीव जैन, मुख्य अभियंता एवं श्री राजीव ज्ञानी, अधीक्षण अभियंता भी उपस्थित रहें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस पुरस्कार के लिए क्रेडा की टीम और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि लगातार 03 वर्षों (वर्ष 2020, 2021 एवं 2022) से क्रेडा को सीम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा विगत 11 वर्षों में प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी, भारत सरकार की च्राज् परियोजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 44 औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदेश में लगभग 2.198 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्वीवेलेंट ऊर्जा की बचत कर लगभग 6.67 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन कम किया गया है। इस परियोजना के तहत प्रदेश के उद्योगों को कुल दस लाख से भी अधिक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। व्यावसायिक भवन क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अधिसूचित किया गया है तथा राज्य में कुल 15 भवनों को ग्रीन भवन के रूप में प्रमाणित किया गया है तथा 8 शासकीय भवनों को स्टार रेटिंग नामित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र शासन को अग्रेषित किया गया है।

भाजपा में बहुत ज्यादा होती है नाटक-नौटंकी: मुख्यमंत्री भूपेश

■ कहा- अब पीएम मोदी मित्रों से परिवारजनों पर आ गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी में नाटक और नौटंकी बहुत ज्यादा होती है। इसे हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी महिला बिल लाई है। इसे 2024 में लागू किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह बिल लाया गया है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब वो मित्रों से परिवारजनों पर आ गए हैं। सब लोग जानने लगे हैं, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है।

सीएम भूपेश बघेल ने पाटन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम कैंसिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि शाह का दौरा लगातार कैंसिल हो जा रहा है, क्या बात है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पाटन में रात्रि विश्राम करने वाली थीं, लेकिन वह भी नहीं आईं। अब केवल बच गए तो

मुख्यमंत्री रघुवर दास।

बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है?, पता ही नहीं चलता

भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में मेंबरशिप होता है, यह पता चलता है, लेकिन उसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, यह पता ही नहीं चलता। कांग्रेस में टिकट वितरण के सवाल पर कहा कि सबसे पहले ब्लॉक और जिला कमेटियों के सुझावों को कांग्रेस कमेटी में रखी जाती है। इसके बाद प्रदेश चुनाव समिति में, फिर स्क्रीनिंग कमेटी में रखी जाती है। सीएम ने बीजेपी के %वन, नेशन वन इलेक्शन% पर कहा कि इसी के लेकर हम देख रहे थे, लेकिन %खोदा पहाड़ निकली चुहिया% वाली कहावत साबित हुई। लोकसभा में महिला बिल पारित हुआ है, वह 2029 में या 2039 में लागू होगा यह भी भरोसा नहीं है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना होगी। फिर इस पर चर्चा होगी।

उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अब वो मित्रों से परिवारजनों पर आ गए हैं। सब लोग जानने लगे हैं, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। आजकल फोन पर भी कॉल आ रहे हैं कि धान केंद्र सरकार खरीदती है। इस संबंध में प्रियंका गांधी ने भिलाई में मंच से कहा था कि यदि के धान केंद्र सरकार खरीदती है तो यूपी के किसान 1200 से लेकर 1400 में धान बेचने के लिए क्यों मजबूर हैं। सीएम ने बीजेपी से सवाल करते हुए पूछा कि रमन सिंह के कार्यकाल में 300 रुपए बोनस सरकार दे रही थी, तो यह पीएम मोदी के कहने पर बंद हुआ? सरकार जब 15 क्विंटल धान खरीद रही थी तो उसे 10 क्विंटल करने के लिए क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था? किसानों को गुमराह नहीं किया जा सकता।

अब इलाज में नहीं होगी कमी, राज्य सरकार ने बढ़ा दी स्वास्थ्य सहायता योजना की राशि

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता राशि को राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। पहले 20 लाख राशि दिए जाते थे। इस बार बढ़ाकर उसे 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए सहायता राशि मिलेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के विगत मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर सीएम विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत सहायता राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का आदेश जारी कर दिया है।

भारत से कुछ तो सीखे पाकिस्तान

मरिआना बाबर

हाल ही में भारत ने लगातार तीन बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जिन पर पाकिस्तान की पैनी नजर रही। सबसे पहले भारत का चंद्रयान-3 चांद के अंधेरे हिस्से (दक्षिणी ध्रुव) की तरफ उतरा, जो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना था। उसके बाद जी-20 शिखर सम्मेलन की तस्वीरें सामने आईं, जिसके कारण दुनिया भर की नजरें नई दिल्ली पर टिकी थीं। और तीसरी घटना यह है कि कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप क्रिकेट मैच जीत लिया! नेपाल ही वह देश है, जहां कई सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जीवित देवी हैं। लेकिन मेरे लिए यह भारत की पंद्रहवीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर थी, जिसमें वह भारतीय देवी की तरह लग रही थीं। यह तस्वीर भारतीय दौरे पर आए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी बैठक के दौरान ली गई थी। तस्वीर में वह अपने सिर पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लेकर शांति से बैठी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने पाकिस्तानियों का ध्यान तब आकर्षित किया था, जब उन्हें पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया था। उन्होंने विशेष रूप से समाज के वंचितों के साथ-साथ हाशिये पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति के विपरीत, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संविधान के दायरे में रहकर और किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ाव से दूर रहते हुए देखना अच्छा है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ (पीटीआई) पार्टी से था, संविधान की मांग के अनुसार अराजनीतिक रहने से इन्कार कर दिया है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें इमरान खान के समर्थक और पीटीआई कार्यकर्ता की तरह काम करते देखा है। हालांकि संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्हें पांच साल के लिए राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था। यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो तब तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, जब तक कि नई सरकार नहीं आती है और वह नई सरकार एक नए राष्ट्राध्यक्ष को नामित नहीं करती। राष्ट्रपति के इस्तीफा देने की स्थिति में, संविधान सीनेट के अध्यक्ष को स्वत: राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने की अनुमति देता है। किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति की गैरमौजूदगी में, सीनेट अध्यक्ष मौजूदा राष्ट्रपति की पूर्ण शक्तियों के साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अतीत में हमने आपातकाल की स्थिति में सीनेट के अध्यक्ष को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते देखा है। यह तब हुआ था, जब 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, इसलिए स्वत: सीनेट के अध्यक्ष गुलाम इशहाक खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए थे। नई दिल्ली से एक और दिलचस्प खबर आई है कि पहली बार किसी भारतीय महिला के रूप में सुश्री गीतिका श्रीवास्तव इस महीने के अंत तक इस्लामाबाद पहुंचकर भारतीय उच्चायुक्त का प्रभार संभालेंगी। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से बाईस पुरुष उच्चायुक्तों के बाद वह पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख होंगी। सुश्री गीतिका सुरेश कुमार से पदभार ग्रहण करेंगी, जो इस महीने के अंत तक पाकिस्तान छोड़ देंगे। सुरेश कुमार की इस्लामाबाद में बहुत कम उपस्थिति देखी गई है और पाकिस्तानी पत्रकारों से वह अक्सर कम मिलते रहे हैं। चाहे द्विपक्षीय संबंध कितने भी खराब क्यों न हों, किसी भी मुल्क में राजनयिकों का काम अपने वतन और तैनाती वाले मुल्क के बीच एक पुल बनाना होता है। वास्तव में जब दो मुल्कों के बीच द्विपक्षीय संबंध खराब होते हैं, तब राजनयिकों के लिए मेजबान देश के लोगों तक पहुंचना और भी जरूरी हो जाता है। बहरहाल, अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि सुश्री गीतिका पाकिस्तानी समुदाय, विशेषकर पत्रकारों तक पहुंच बनाएंगी या नहीं। वर्ष 2019 में कश्मीर मुद्दे पर दोनों पड़ोसी मुल्कों के द्विपक्षीय रिश्तों में गिरावट आने के बाद से नई दिल्ली या इस्लामाबाद में कोई पूर्णकालिक उच्चायुक्त नहीं है। इस पद को कमतर करके अब प्रभारियों के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद में अंतिम पूर्णकालिक भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया थे, जिन्हें 2019 में निष्कासित कर दिया गया था। बाद में वह कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने और उसके बाद सेवानिवृत हो गए।

आधी आबादी को आरक्षण का फार्मूला ?

अनिल तिवारी

पिछले 27 साल से अधर में झूल रहे राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी विषयक विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में भारी बहुमत तथा राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित होते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को कानूनी दर्जा हासिल हो गया है।

राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह विधेयक मील का पत्थर साबित हो सकता है, यह ठीक भी है और इस बात में दम भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यह विधेयक समाज में स्त्री पुरुष बराबरी का लक्ष्य हासिल करने की गरज से लाया गया है तो आधी आबादी को तिहाई आरक्षण देने के निहितार्थ क्या है? लगभग 48.5% महिला आबादी के लिए 33% आरक्षण का फार्मूला कहां से आया?

महिला आरक्षण को लेकर भारत की घरेलू राजनीति तो अक्सर गरम रही, बाहरी दबाव के कारण भी इसे अब और अधिक दिन तक नहीं टाला जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं पर केंद्रित चार विश्व सम्मेलन आयोजित किए गए, जो क्रमश: 1975 में मेक्सिको में, 1980 में कोपेनहेगन में, 1985 में नैरोबी में और 1995 में बीजिंग में हुए। अंतिम सम्मेलन के दौरान बीजिंग घोषणा पत्र जारी किया गया और सभी सदस्य देशों से उस पर त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की गई। सम्मेलन में शामिल सभी 189 देशों द्वारा सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को अपनाया गया और त्वरित कार्रवाई करने का वचन दिया गया। बीजिंग घोषणा पत्र में एक प्रमुख प्रावधान महिलाओं के लिए आरक्षण का भी था।

भारत में महिला आरक्षण की मांग पहले से ही चल रही थी। बीजिंग सम्मेलन के बाद भारत की सरकारों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर रुचि दिखानी शुरू कर दी। यह अलग बात है कि जब भी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को पास करने की कोशिश की तो उसे पिछड़ी जाति के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। पिछड़ी जाति के नेताओं ने इसे हमेशा संसद में उच्च जाति की साजिश के रूप में देखा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान भी यह विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ लेकिन जब यह लोकसभा में पहुंचा तो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जैसे नेताओं ने अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा इसमें नहीं होने की बात उठाते हुए इसका कड़ा विरोध किया था।

दरअसल, महिला आरक्षण का मकसद विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है, इसलिए कुछ लोगों का विचार यह भी रहा है कि महिलाओं को आरक्षण के जरिए ही क्यों आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, उन्हें अपने दम पर आगे आने का मौका देना चाहिए। इसलिए एक विचार यह भी आया कि राजनीतिक दल खुद अपने सांगठनिक ढांचे में एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था लागू करें। मगर हैरानी की बात है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के सैद्धांतिक विचार का समर्थन तो सभी दल करते हैं, चुनावी सभाओं में हमेशा इसकी मांग सभी दोहराते हैं, मगर संगठन के स्तर पर इसे आगे बढ़ाता कोई नजर नहीं आता।

ऐसे विचार जब व्यावहारिक रूप लेते नहीं दिखे तो सिफारिश की गई कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी जाए। इसके लिए मसौदा भी तैयार किया गया। मसौदा तैयार करते समय भी आमतौर पर यह सवाल उभरा कि जब महिलाओं की आबादी 50% है तो 33 प्रतिशत आरक्षण का आधार क्या हो? तब मोटे तौर पर पूर्व में हुए कुछ अध्ययनों के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिशतता तय की गई।

पहला, एक अध्ययन में पाया गया कि किसी भी संस्थान में महिलाओं की मौजूदगी वहां की गुणवत्ता में सुधार लाती है। उदाहरण के लिए पुलिस जैसे संस्थानों में महिलाओं की बढ़ती संख्या पुलिस हिंसा को कम करने में कारगर साबित हुई है। भारी संख्या में महिला पुलिस होने के कारण खासकर महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले दबे कुचले लोगों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसी अध्ययन में यह भी निकल कर आया है कि किसी भी संस्था की कुल संख्या में महिलाओं की उपस्थिति अगर एक तिहाई से अधिक होने लगती है तो इसका प्रभाव संस्था पर सीधे तौर पर पड़ने लगता है। इसे ध्यान में रखते हुए महिलाओं की जनसंख्या 50त्न होने के बावजूद केवल 33त्न आरक्षण का प्रस्ताव मसौदे में किया गया।

दूसरा, राजनीति का क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य संस्थान, सीट आरक्षित न होने की दशा में कुछ गिनी चुनी नाम मात्र की महिलाएं तो आगे बढ़ जाती हैं और कई बार लंबे समय तक पद पर काबिज रहती हैं। ऐसी महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए बैरियर का काम करने लगती हैं। माना गया कि एक तिहाई आरक्षण से यह बैरियर भी टूटेगा।

तीसरा, संसद और विधानसभा में आरक्षण की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पारंपरिक रूप से स्त्रियों के कुछ बंधे हुए काम माने गए। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के बारे में यह धारणा बनाई गई कि औरतें राजनीति की कठिनाइयां नहीं झेल सकती। एक सीमा तक इस समस्या का भी हल एक तिहाई आरक्षण में दिखा।

सरकार द्वारा तैयार महिला आरक्षण विधेयक की अब तक की यात्रा काफी रोचक और रोमांचक रही है। साल 1996 में तैयार किया गया यह विधेयक प्रारंभ से ही विवादों में उलझा रहा है। पहली बार तो विरोधी दल के नेताओं ने इसे पेश ही नहीं करने दिया। उसके बाद 1998 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री आई के गुजराल ने कोशिश की तो उनकी ही पार्टी के लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। सरकार में मंत्री रहे शरद यादव ने आधी आबादी के लिए परकटी महिलाओं जैसा जुमला भी उछाला। उसी साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे पेश करने की कोशिश की लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसे सदन में ही फाड़ डाला। इस खींचातानी में तत्कालीन कानून मंत्री थंबी दुरई की कमीज भी फट गई थी।

फिर वर्ष 2000 में विधेयक पेश किया गया लेकिन पास नहीं हो सका। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महिला आरक्षण पर सहमति के लिए 3 मार्च 2002 को सभी दलों की बैठक बुलाई, बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई क्योंकि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की पार्टी पिछड़ों के लिए अलग से कोटा की मांग पर अड़ी रही। मनमोहन सरकार ने भी इस विधेयक को लेकर कोशिश की, पर वह भी इसे सिर्फ राज्यसभा में ही पास करवा सके।

वर्ष 2014 में राजग सरकार बनने के बाद 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। अब संसद के नवनिर्मित भवन से ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर बेटियों के लिए राजनीति करने और चुनकर लोकसभा तथा विधानसभाओं में पहुंचने का दरवाजा खोल दिया है। हालांकि अभी अगले 15 साल तक के लिए 50 फ़ीसदी आबादी के बरक्स 33% आरक्षण का प्रावधान कानून में किया गया है। फिर भी इस हिस्सेदारी को राजनीतिक घटतौली के रूप में देखने की बजाय सकारात्मक सोच के साथ लिया जाना चाहिए।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

पाशुपतब्रह्मोपनिषद् (भाग-13)

गतांक से आगे...

बाह्य एवं आभ्यन्तर कारणों के रूप ग्रहण की योग्यता ही आवाहन हैं। उसका बाह्य एवं आभ्यन्तर करणों (इन्द्रियों) का एक रूप होकर विषयों का ग्रहण करना ही आसन है। रक्त एवं शुक्ल पद (सत एवं तम गुणों) का एकीकरण पाद्य है। उ'वल (निर्मल) दामोदानन्द (आनन्दमय ब्रह्म) में सदैव अवस्थित रहने तथा इसी का दान (योग्य शिष्य को यह ज्ञान प्रदान करना) - अर्घ्य है। स्वयं स्व'छ एवं स्वत: सिद्ध होना ही आचमन है।

चिद्रूप चन्द्रमयी शक्ति से सम्पूर्ण अंगों का स्त्रवण (स्वेदयुक्त होना) ही स्नान है। चिद् अग्निस्वरूप परमात्मा की शक्ति का स्फुरण (प्रकाशित होना) ही वस्त्र है। (इ'छा-ज्ञान-क्रिया आदि तीन शक्तियों के त्रिगुणात्मक होने से) हर एक के जो सत्ताईस भेद एवं इ'छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति स्वरूप ब्रह्म, (विष्णु एवं रुद्र) ग्रन्थि के मध्य स्थित सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्मसूत्र है, (क्योंकि यही नाड़ी ब्रह्म की द्योतिका है।) अपने से पृथक् वस्तु का स्मरण न करना ही आभूषण है। शुभ्र स्वरूप, जो ब्रह्म है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, यही स्मरण करना गन्ध है। समस्त विषयों का मन की स्थिरता द्वारा अनुसन्धान करना ही पुष्प (फूल) है तथा उसे स्वीकार करना ही धूप है। पवनयुक्त योग के समय प्राण, अपान की एकता से सुषुम्ना में सत-चित् उल्कारूप जो (प्रकाशरूप) आकाश देह है, वही दीप है। अपने से अलग समस्त विषयों में मन की गति का गमनागमन स्थिर हो जाना ही नैवेद्य है। तीनों अवस्थाओं (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) का एकीकरण ही ताम्बूल (पान) है। मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त एवं ब्रह्मरन्ध्र से मूलाधार तक बार-बार आना-जाना ही प्रदक्षिणा है। चतुर्थ अवस्था अर्थात् तुरीयावस्था में रहना ही नमस्कार है। देह की जड़ता में डूबना अर्थात् आत्मा को चैतन्य युक्त मानकर एवं शरीर को जड़ मानकर स्थिर रहना ही बलि है। अपना आत्मतत्त्व ही स्वयं सत्य रूप है, ऐसा निश्चय करके कर्त्तव्य, अकर्त्तव्य, उदासीनता, नित्यात्मक आत्मा में विलास करना अर्थात् निरन्तर आत्मचिन्तन करना ही यज्ञ (हवन) है तथा स्वयमेव उस परब्रह्म विराट् पुरुष (परमात्मा) की पादुकाओं में अनासक्त भाव से डूबे रहना ही परिपूर्ण ध्यान है। (सारांश यह हुआ कि जिस प्रकार पूजन के लिए धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा एवं नमन-वन्दन आदि अपेक्षित होता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपर्युक्त कहे गये पदार्थों का साधन कर लेना ही सद्सद् धूप-दीप एवं नैवेद्य आदि हैं। इन्हीं मांगलिक पदार्थों को भावनापूर्वक समर्पित करने से ही उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है)। इस तरह से जो भी मनुष्य (योगी-साधक) तीन मुहूर्त तक भावनापरायण रहता है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है। वह एक मात्र ब्रह्म का ही रूप हो जाता है तथा उसके द्वारा चाहे हुए कार्य बिना यत्र के ही पूर्ण हो जाते हैं और वही (साधक) शिवयोगी कहलाता है।

क्रमश: ...

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय

डॉ. राकेश मिश्र

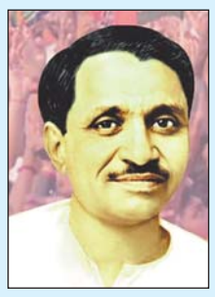

अपने उच्च विचारों, आदर्शों और त्याग के कारण भारत के लोगों के हृदय में स्थान बनाने वाले और एकात्म मानववाद जैसी विचारधारा और राष्ट्रवादी चिंतन देनेवाले, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ व राष्ट्रीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता भारत के सबसे तेजस्वी एवं यशस्वी चिंतकों में से एक रहे हैं।

25 सितम्बर सन् 1916 को चंद्रभान, फ़राह, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। 1937 में कानपुर में अपनी बी.ए. की पढ़ाई के दौरान वे अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे और सुंदर सिंह भंडारी के साथ मिलकर समाज सेवा करने लगे। इन्ही दिनों वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार व भाऊराव देवरस से संपर्क में आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर संघ से जुड़ गए।

भाऊराव देवरस से प्रेरणा पाकर सन 1947 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लखनऊ में राष्ट्रधर्म प्रकाशन स्थापित किया, जिसके अंतर्गत मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म प्रकाशित एवं प्रसारित की जाने लगी। बाद में पांचजन्य साप्ताहिक और दैनिक समाचार पत्र

स्वदेश का भी प्रकाशन यहां से हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक अच्छे साहित्यकार व लेखक भी थे। 1946 में जब संघ से जुड़े किशोरों तक अपनी विचारधारा सरल शब्दों में पहुंचाने की बात आयी तो पंडित जी ने बिना किसी से कुछ कहे रातभर जागकर चाणक्य और सम्राट चन्द्रगुप्त को केंद्र में रखकर सम्राट चन्द्रगुप्त नाम से एक उपन्यास लिख डाला। अपने जीवन में सफ़लता की अनेक सीढियां चढ़ने के बाद पंडित जी ने स्वयं को पूर्ण रूप से देश के प्रति अर्पित कर दिया। 21 अक्टूबर सन् 1951 में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की तो 1951 से 1967 तक वे भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 29 दिसम्बर 1967 को उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। विडम्बना ही कही जायेगी कि पंडित जी सिर्फ 44 दिनों तक ही बतौर अध्यक्ष कार्य कर पाए। पंडित जी ने प्रथम अधिवेशन में ही अपनी वैचारिक क्षमता का परिचय देते हुए सात प्रस्ताव प्रस्तुत किये और सभी को पारित कर दिया गया। उनकी कार्यक्षमता, परिश्रम और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था- यदि मुझे ऐसे दो दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश का राजनीतिक मानचित्र बदल दूंगा। डॉ. साहब की यही बातें पंडित जी का हौंसला और भी बढ़ाती गई। पंडितजी राष्ट्रनिर्माण व जनसेवा में इतने लीन थे कि उनका कोई व्यक्तिगत जीवन ही नहीं रहा, बांकी का जीवन संघ और जनसंघ को मजबूत बनाने और इन संगठनो के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने में अर्पित कर दिया।

उनकी अवधारणा और चिंता का विषय था कि लम्बे समय तक की गुलामी के पश्चात कहीं पश्चिमी विचारधारा भारतीय संस्कृति पर हावी न हो जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था, परन्तु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मन में भारत के विकास को लेकर चिंता थी। वे मानते थे कि लोकतंत्र भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार है न कि अंग्रेज़ो का एक उपहार। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्रजीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्वदृष्टि प्रदान करना था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। उन्हें जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार माना जाता है। उनका विचार था कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है।

सनातन धर्म को द्रविड़ परंपराओं ने कैसे बदला

मृत्युंजय कुमार राय

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में सनातन धर्म की तुलना डेंगी, मच्छर, मलेरिया, और कोविड से की। उसके बाद उनकी पार्टी छ्रू्य के सांसद ए राजा ने कहा कि हिंदू धर्म 'न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए अभिशाप है।' इन छ्रू्य नेताओं के बयानों से जब विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई तो दी, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहे। उदयनिधि ने कहा कि उन्होंने सनातन धर्म की बुराइयों को खत्म करने की बात कही है, न कि इसे मानने वालों को। उन्होंने इस सिलसिले में छुआछूत और जातिवाद का जिक्र किया। वहीं, राजा ने कहा कि उन्होंने तो डॉ. भीमराव आंबेडकर की कही बातें ही दोहराई हैं, इसलिए इस पर हो-हल्ले की जरूरत नहीं है।

इन बातों की जड़ें तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी हैं, जहां पेरियार की सामाजिक न्याय की लड़ाई का असर कई दशकों से रहा है और आगे भी बना रहेगा। लेकिन राजनीति और धर्म के रिश्ते पर बात करने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि सनातन धर्म और द्रविड़ पहचान का अर्थ क्या है। जिस तरह से राजनेता इसे लेकर विवाद खड़े कर रहे हैं, क्या वाकई उसका कोई आधार है? पहली बात तो यह है कि हिंदू धर्म हजारों वर्षों में विकसित हुआ और इसमें कई धार्मिक, सांस्कृतिक धाराएं जुड़ीं और उस पर कई दर्शनों का प्रभाव भी दिखता है।

दूसरी ओर, एथनिक समूह के रूप में द्रविड़ पहचान हिंदू धर्म की तुलना में कहीं नई है। असल में, द्रविड़ पहचान का सांस्कृतिक और भाषाई आधार है, इसकी कोई धार्मिक बुनियाद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कुछ भाषाओं को उनके जन्म के आधार पर इंडो-आर्यन भाषाओं से अलग मानकर द्रविड़ भाषाओं की पहचान बहुत बाद में दी गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस पहचान से पहले इन लोगों की धार्मिक मान्यताएं नहीं थीं। द्रविड़ लोगों का धर्म क्या था और उनकी पूजा पद्धति क्या थी, इसका जवाब आगम साहित्य से मिलता है। कुछ जानकार मानते हैं कि इसकी रचना वेदों के लिखे जाने से पहले की है तो कुछ का दावा है कि इसे वेदों के बाद लिखा गया है।

लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आगम सनातन धर्म का गैर-वैदिक रूप है। हिंदू धर्म की इसी धारा को द्रविड़ लोग मानते थे। आगम में तमिल और संस्कृत भाषा में लिखी गई बातें शामिल हैं। इसमें पूजा के तरीके, ध्यान, दर्शन, मंदिर और मूर्ति बनाने के तरीके आदि दिए गए हैं। हिंदू धर्म में प्रकृति और देवी पूजा का जो रूप आज तक बना हुआ है, उसे द्रविड़ धर्म का ही प्रभाव माना जाता है। इसका अर्थ यही है कि हिंदू और द्रविड़ धर्म काफी पहले ही मिल गए थे और उन पर एक दूसरे का असर पड़ना शुरू हो गया था। इसका प्रमाण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसमें संस्कृत के साथ द्रविड़ भाषा के शब्द भी हैं। भाषा विज्ञानी एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति के असर का पता दोनों के बीच भाषाई आदान-प्रदान के आधार पर ही लगाते हैं।

वैसे, द्रविड़ लोगों की धार्मिक परंपराओं को लेकर जानकारों में मतभेद भी हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि नवपाषाण काल में दक्षिण एशिया में द्रविड़ लोगों में आस्था का जो स्वरूप था, वह कहीं और नहीं दिखता। जो लोग यह सोच रखते हैं उनका दावा है कि यह इंडो-आर्यन भाषाओं से जन्म लेने से पहले की बात है। दूसरी ओर, कुछ विद्वानों का कहना है कि ऋग्वेद के लिखे जाने से पहले यानी 1500 ईसा पूर्व में द्रविड़ धर्म जैसी कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं थी। वहीं, कुछ जानकारों के मुताबिक, यह हिंदू धर्म का ही गैर-वैदिक रूप था।

इस मामले में भले ही विद्वानों की राय अलग-अलग हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्य भाषा बोलने वालों के धर्म और द्रविड़ लोगों की धार्मिक परंपराओं के बीच व्यापक मेल हुआ। इस पर आदिवासी धर्मों का भी प्रभाव पड़ा। इन सबके मिलने से ही हिंदू धर्म का आधुनिक स्वरूप उभरा, जिसे आज लोग मानते हैं। गौर करने की बात यह भी है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ गांवों में जिस तरह से आज भी देवियों की पूजा की जाती है, वह द्रविड़ धर्म की पुरानी परंपराओं का ही अटूट सिलसिला है। शक्ति की उपासना इस धर्म की खास बात है, जिसने हिंदू धर्म को गहरे प्रभावित किया। आज द्रविड़ भाषी समाज में भी किसी द्रविड़ धर्म की अवधारणा नहीं है। वहां के बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी हिंदू धर्म की कमोबेश वही मान्यताएं हैं, जो उत्तर भारतीय बहुसंख्यकों के लिए। अगर कोई फर्क दिखाने की कोशिश होती है तो उसके पीछे राजनीति और धर्म का वह घालमेल है, जिसने सनातन धर्म को लेकर हालिया विवाद को जन्म दिया है।

असल में लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक दलों को हमेशा ऐसे भावनात्मक मुद्दों की तलाश रहती है, जिससे बड़े पैमाने पर वोटरों को प्रभावित किया जा सके। धार्मिक मुद्दे इस पैमाने पर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक मुद्दों का हमेशा राजनीतिक फायदा हो ही। हां, अयोध्या का मामला ऐसा जरूर रहा है, जिसका बीजेपी को बड़ा राजनीतिक फायदा मिला। ऐसे ही मुद्दे की तलाश में जातीय समूहों की राजनीति भी हुई, जिसका कुछ राजनीतिक दलों को लाभ हुआ। आज भी जातीय आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, साथ ही जातीय जनगणना के जरिये मंडल वाले दौर की तरह राजनीतिक कामयाबी को दोहराने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन धर्म हो या जाति, उनके जरिये इतिहास दोहराने की कोशिश पहले की तरह शायद ही सफल हो।

हिन्द स्वराज्य

सच्ची सभ्यता कौन सी ? (भाग-3)

गतांक से आगे...

प्रश्न- आपने जैसा बताया वैसा ही हिन्दुस्तान होता तब तो ठीक था। लेकिन जिस देशमें हजारों बाल विधवाएं हैं, जिस देश में दो बरस की बच्ची की शादी हो जाती है, जिस देश में बारह साल की उम्र के लड़के-लड़कियाँ घर-संसार चलाते हैं, जिस देश में स्त्री एक से ज्यादा पति करती है, जिस देश में नियोग की प्रथा है, जिस देश में धर्म के नाम पर कुमारिकाएँ वेश्याएँ बनती हैं, जिस देश में धर्म के नाम पर पाड़ों और बकरों की हत्या होती है, वह देश भी हिन्दुस्तान ही है। ऐसा होने पर भी आपने जो बताया वह क्या सभ्यता का लक्षण है?

उत्तर- आप भूलते हैं। आपने जो दोष बताये वे तो सचमुच दोष ही हैं। उन्हें कोई सभ्यता नहीं कहता। वे दोष सभ्यता के बावजूद कायम रहे हैं। उन्हें दूर करने के प्रयत्न हमेशा हुए हैं, और होते ही रहेंगे। हममें जो नया जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग हम इन दोषों को दूर करने में कर सकते हैं। मैंने आपको आज की सभ्यता की जो निशानी बतायी, उसे इस सभ्यता के हिमायती खुद बताते हैं। मैंने हिन्दुस्तान की सभ्यता का जो वर्णन किया, वह वर्णन नयी सभ्यता के हिमायतियों ने किया है। किसी भी देश में किसी भी सभ्यता के मातहत सभी लोग संपूर्णतातक नहीं पहुँच पाये हैं। हिन्दुस्तान की सभ्यता का झुकाव नीति को मजबूत करने की ओर है; पश्चिम की सभ्यता का झुकाव अनीति को मजबूत करने की ओर है, इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिमकी सभ्यता निरीश्वरवादी है, हिन्दुस्तान की सभ्यता ईश्वर में मानने वाली है। यों समझकर, ऐसी श्रद्धा रखकर, हिन्दुस्तान के हितचिंतकों को चाहिए कि वे हिन्दुस्तान की सभ्यता से, बच्चा जैसे माँसे चिपटा रहता है वैसे, चिपटे रहें।

कर्नाटक में हाथ तो मिला लिया, क्या दिल भी मिलेंगे?

समीर चौगांवकर

कुछ दिन पूर्व ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता येदियुरप्पा ने इस बात का खुलासा किया था कि जेडीएस भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। आखिरकार शुक्रवार को दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में कुमारस्वामी ने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है और आने वाला लोकसभा चुनाव वह भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी।

फिलहाल दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि खबर है कि जेडीएस कर्नाटक की मांड्या, हासन, बेंगलुरु (ग्रामीण) और चिकबल्लापुर लोकसभा सीट के अलावा विधान परिषद में दो सीटें या राज्यसभा की एक सीट की मांग भाजपा के सामने रखी है। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने चार लोकसभा और एक विधान परिषद की सीट जेडीएस को देने का भरोसा दिया है।

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस के खाते में एकमात्र हासन सीट आई थी, जहां से एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने चुनाव जीता था, लेकिन 1 सितंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में दोषी करार देते हुए उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया था। प्रज्वल की सांसदी रद्द होने के बाद अब लोकसभा में जेडीएस का कोई सांसद नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस को 9.67त्न वोट और एक सीट मिली थी।

दरअसल, जनता दल सेक्यूलर को कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी कहने से बेहतर जेडीएस को दक्षिण कर्नाटक तक सीमित पार्टी कहा जा सकता है। यह इलाका ओल्ड मैसूर के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में हासन, मांड्या, रामनगर, तुमकुरू, मैसूर और दक्षिण के अन्य जिले आते हैं। यहां जेडीएस का प्रभाव तो है लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में यहां का मतदाता कांग्रेस के साथ चला गया था।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत का कारण यह भी था कि भाजपा का परंपरागत वोटर लिंगायत और दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस का परंपरागत मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ चला गया था। कांग्रेस के 34 लिंगायत विधायक चुनाव जीते हैं।

कर्नाटक में 30 साल में पहली बार कांग्रेस के इतने लिंगायत विधायक जीतकर आए हैं। कांग्रेस ने इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा से 53 सीटें छीनी हैं और 59 सीटें बचाई हैं। कांग्रेस को 43 प्रतिशत वोट मिले। यह वोट शेयर के लिहाज से 1989 के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। भाजपा के बुरे प्रदर्शन का आलम यह रहा कि कर्नाटक जैसे मजबूत गढ़ में भी भाजपा की 31 सीटों पर जमानत जब्त हो गयी थी।

निश्चित रूप से कांग्रेस ने कर्नाटक के सभी क्षेत्रों में भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया था। मुम्बई कर्नाटक जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहां से आने वाली 50 सीटों में से कांग्रेस ने 33 सीटें जीती जबकि भाजपा को अपने गढ़ में सिर्फ 16 सीटें मिली। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से जिसे कांग्रेस और जेडीएस के प्रभाव का क्षेत्र कहा जाता है यहां भाजपा सेंध लगाने में असफल रही। कांग्रेस ने इस क्षेत्र से आने वाली 40 सीटों में से लगातार तीसरी बार आधे से ज्यादा सीटें अपने नाम की। कांग्रेस को यहां से 26 सीटें मिली जबकि भाजपा को महज 10 सीटें मिली। जेडीएस भी यहां 3 सीटें जीतने में सफल रही थी।

भाजपा के गढ़ मध्य कर्नाटक से आने वाली 23 सीटों में से कांग्रेस को 15 सीटें, भाजपा को 6 और जेडीएस को 1 सीट मिली थी। अब भाजपा से हाथ मिलाने वाली जेडीएस के गढ़ ओल्ड मैसूर की 64 सीटों में से कांग्रेस ने अकेले 43 सीटें, भाजपा ने 5 सीटें और जेडीएस ने सिर्फ 14 सीटें जीती। अपने मुस्लिम वोटरों को ध्यान में रखते हुए जेडीएस ने सर्वाधिक 23 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे लेकिन जेडीएस का एक भी मुस्लिम प्रत्याशी जीत नहीं सका। जेडीएस को राज्य में सिर्फ 19 सीटें मिली।

2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कर्नाटक में 51.75 फीसदी वोट के साथ 25 सीटें जीतीं थी। गठबंधन में रहने के बाद भी कांग्रेस और जेडीएस को एक-एक सीट से संतोष करना पड़ा था। भले ही भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस 18 लोकसभा सीटों पर आगे थी और भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर आगे रही। विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर देखें तो हासन और तुमकुरु जेडीएस के खाते में जाते हुए दिख रही हैं।

लेकिन यह पहली बार नहीं है जब कर्नाटक में दोनों दल एक साथ आये हैं। भाजपा और जेडीएस का गठबंधन 2006 में भी हो चुका है। हुआ यूं था कि 2004 के विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई और धरम सिंह मुख्यमंत्री बने लेकिन 2006 में जेडीएस ने गठबंधन तोड़ दिया और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लिया। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। लेकिन वादे के मुताबिक भाजपा को डेढ साल बाद मुख्यमंत्री का पद देने के वादे से मुकरते हुए जेडीएस भाजपा गठबंधन से बाहर हो गई और कर्नाटक में फिर से विधानसभा चुनाव करवाने पड़े थे।

दक्षिण के अपने प्रवेशद्वार कर्नाटक में सत्ता से बाहर हो चुकी बीजेपी किसी भी स्थिति में कुछ ही माह बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की 25 सीटों को बरकरार रखना चाहती है। लेकिन बदली परिस्थितियों में अकेले के दम पर बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा नहीं सकती। ऐसे में लोकसभा चुनाव में 25 सीट जीतनेवाली भाजपा और लोकसभा में नदारद हो चुकी जेडीएस के सामने राजनीतिक मजबूरी है कि कांग्रेस को रोकने तथा अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए आपस में हाथ मिलायें।

परंतु जेडीएस और भाजपा दोनों जानते हैं कि दोनों ने हाथ मिलाए हैं दिल नहीं। ऐसे में अवसरवाद का यह गठबंधन कितने दिन चलता है, यह भविष्य बताएगा लेकिन दोनों के साथ आने से एक बात साबित हो गयी है कि मोदी की लोकप्रियता को लेकर भाजपा कितने भी दावे करे, कर्नाटक में कांग्रेस का भय उसे सता रहा है। जेडीएस और भाजपा का यह गठबंधन कर्नाटक में कांग्रेस की जमीनी ताकत को भी बयां कर रहा है कि मजबूरी में ही सही दोनों को हाथ मिलाना पड़ा। फिर देवगौडा परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और कुमारस्वामी के खिलाफ मुख्यमंत्री रहते भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित है। ऐसे में जेडीएस के पास भाजपा के साथ जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं था।

चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर सबको चौंका सकती हैं मायावती

स्वदेश कुमार

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बड़ा चुनावी फैक्टर बन गयी है। बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं जिसके चलते राजनीति के गलियारो में हड़कम्प मचा हुआ है। वैसे तो पिछले दो दशकों में बसपा लगातार कमजोर हुई है, लेकिन अभी भी उसके पास 14 फीसदी दलित वोट बैंक मौजूद है। इसी के चलते बसपा से सब हाथ मिलाना चाहते हैं, तो मायावती को भी अपनी इस ताकत पर गुमान है, जिसके चलते वह फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही हैं, तो बसपा से हाथ मिलाने को इच्छुक नजर आ रहा एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों गठबंधन के नेताओं ने हार मान ली हो। सूत्र बताते हैं कि गुपचुप तरीके से मायावती को अपने खेमे में लाने के लिए दोनों गठबंधन दलों के आकाओं द्वारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भाजपा और कांग्रेस गठबंधन से दूरी बनाकर चलने के चलते आईएनडीआईए गठबंधन को यूपी में लोकसभा की 80 सीटों पर करारा झटका लग सकता है। ऐसे में आईएनडीआईए एक बार फिर मायावती पर डोरे डालने में लग गया है। बसपा नेत्री मायावती से गुपचुप तरीके से बातचीत की जा रही है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन यूपी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। बताते चलें कि बसपा के बिना सपा-कांग्रेस एक साथ मिलकर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ के देख चुके हैं जिसका कोई फायदा इन दोनों दलों को नहीं हुआ था इसीलिए इस बार मायावती को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बसपा को साथ लाने की कोशिश में यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। अभी तक यह बातचीत अपने मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन तब से दोनों के बीच संवाद बना हुआ है। इसमें गांधी परिवार और उसके करीबी शामिल हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच गठबंधन को लेकर गुप्त रूप से चर्चा भी हो चुकी है। बसपा की ओर से उसके एक पूर्व सांसद की भी इस बातचीत में अहम भूमिका है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा-कांग्रेस की गठबंधन की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई थीं। तब तय हुआ था कि विधानसभा की 125 सीटों पर कांग्रेस और शेष 278 सीटों पर बसपा लड़ेगी। खबरें लीक हुईं और फिर सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गईं कि दोनों ही दलों को कदम पीछे खींचने पड़े। चुनाव के बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि हम बसपा को आगे रखकर यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, पर वह तैयार नहीं हुई। इस बार लोकसभा चुनाव के ऐन पहले ही आधिकारिक रूप से घोषणा करने की रणनीति है। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि क्या आईएनडीआई गठबंधन में बसपा के आने से सपा सहज रहेगी, इसका जवाब मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व, यूपी में बसपा को साथ लाने में ज्यादा रुचि ले रहा है। इसकी वजह है कि बसपा के पास अभी भी 14 फीसदी दलित वोट बैंक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बागेश्वर (उत्तराखंड) विधानसभा सीट को लेकर सपा के खिलाफ दिया गया बयान भी इसी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अजय राय ने यह बयान हाईकमान से इशारा मिलने के बाद ही दिया था। संभावना जताई जा रही है कि जैसे-जैसे कांग्रेस की बसपा के साथ बात आगे बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे इस तरह के और बयान भी आ सकते हैं। गांधी परिवार के नजदीकी नेता के मुताबिक वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ कांग्रेस के अनुभव अच्छे नहीं रहे। उस चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कहते रहे, लेकिन 145 सीट देने के वादे के बावजूद कांग्रेस को 105 सीटें दी गईं। इसमें से करीब 10 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी को पंजे पर चुनाव लड़वाया था। बहरहाल, जिस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन में बसपा को लाने की कोशिश की जा रही है, उससे बसपा अपर हैंड में नजर आ रही है।

नेहरु-इंदिरा से लेकर इंडिया गठबंधन तक पत्रकारिता पर पहरेदारी क्यों?

आनंद कुमार

स्वतंत्र भारत में संविधान का पहला संशोधन ही पत्रकारिता को नियंत्रित करने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए हुआ था। भारत स्वतंत्र हुआ ही था और उस समय शरणार्थियों को लेकर जो सरकारी नीतियां थीं, उनका आर्गेनाइजर जैसे पत्र विरोध कर रहे थे। पहले तो सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वो पाकिस्तान के विरुद्ध समाचार छापने से पहले सरकार की अनुमति लें, मगर जब बात नेहरु और जिन्ना के एक कार्टून छाप देने तक पहुंची तो मुकदमा हो गया और मामला अदालतों में जा पहुंचा। शीर्ष अदालत में जब संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आर्गेनाइजर का ही पक्ष लिया तो प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान में संशोधन करना तय कर लिया। इसके बाद संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक आया जिस पर सोलह दिन बहस चली। लंबी बहस के बाद आखिरकार 18 जून 1951 को संविधान के पहले संशोधन के साथ ही पत्रकारिता को नियंत्रित करने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने का उपाय कर दिया गया। आगे इसका नतीजा फिल्मों-किताबों पर प्रतिबन्ध के रूप में दिखा। इसी के नतीजे में कवियों, शायरों, पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई। इंदिरा गांधी द्वारा थोपी गई इमरजेंसी का तो पूरा इतिहास ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का रहा है। अभी लोग कहां भूले हैं कि अखबारों को खबर छापने से पहले सरकार को दिखानी पड़ती थी। लेकिन यह अजीब संयोग है कि सत्ता में रहते हुए जिन्होंने पत्रकार और पत्रकारिता को नियंत्रित करने का प्रयास किया, वही लोग अब विपक्ष में बैठकर पत्रकारों के बहिष्कार की नीति अपना रहे हैं। अगर आज का सत्तापक्ष अमृत काल की बात कर रहा है तो विपक्ष अपने सेंसर काल को लागू करने पर अमादा है। सवाल ये है कि जो कल तक बॉयकॉट को नफरती चिंटूओं का औजार बताते थे, वो आज नए तर्क गढ़कर उसी का समर्थन करने कैसे उतरे हैं? राहुल गांधी व्यक्तिगत संबोधनों में टीवी पत्रकारों पर हमलावर थे लेकिन इंडिया गठबंधन भी पत्रकारों और न्यूज एंकरों के बहिष्कार का ऐलान करेगा ये थोड़ा चौंकाने वाला था। लेकिन दिल्ली के महंगे हयात होटल में इंडिया गठबंधन की बैठकों के बाद से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था। जिस तेजी से होटल में मिलने वाले पानी की कीमत का लोगों को पता चल रहा था, उसी तेजी से पत्रकारों और चैनलों पर प्रतिबन्ध की ख़बरें भी आने लगी थीं। शुरू में कहा तो ये जा रहा था कि कुछ चैनलों पर ही सीधा प्रतिबन्ध लगेगा, लेकिन विपक्ष ने वैसा कुछ किया नहीं। फिर खबर आने लगी कि 34 पत्रकारों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, लेकिन अंततः जब बयान जारी हुआ तो केवल 14 ही नाम सामने आये। जिस आरोप में कुछ ख़ास लोगों के टीवी डिबेट में शामिल न होने का इंडिया गठबंधन ने फैसला किया वो आरोप हिन्दू-मुस्लिम मुद्दों पर चर्चा करने का और नफरत की राजनीति करने का था। ये बड़ा विचित्र आरोप था क्योंकि हाल ही में मुजफ्फरनगर में एक स्कूल टीचर द्वारा बच्चे की पिटाई के वीडियो में हिन्दू-मुस्लिम का कोण तो इंडिया गठबंधन वाले निकालकर सामने लाये थे। यद्यपि पत्रकारों से पक्षपात के आरोप अक्सर भाजपा पर चिपकाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी विरोधी कहलाने वाली पार्टियों का पत्रकारों पर हमले करने का लम्बा इतिहास रहा है। अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो इसी वर्ष जनवरी में पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र पर जारी मुक़दमे को ख़त्म किया था।

भाजपा तीनों राज्यों में पूर्व सीएम को कैसे करेगी मैनेज

राहुल संपाल

साल के अंत में पांच राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होना है। राज्यों के इन चुनावों को 2024 के सेमीफाइनल के तौर देखा जा रहा है। इन सूबों में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही हैं। मध्यप्रदेश में भाजपा जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा के जरिए सियासत साधने की कोशिश की जा रही है। हिंदी पट्टी के तीनों अहम राज्यों में भाजपा-कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनावी दौरे शुरु हो गए हैं। भाजपा इन राज्यों के संगठन के पेंच कस रही है। वहीं परंपरागत वोट बैंक को अपने हक में करने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन इन तीनों ही राज्यों में तीन पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ये तीनों पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खुलकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी पसोपेश में है। राजे पार्टी पर चुनाव में उनकी भूमिका स्पष्ट करने को लेकर दिल्ली दरबार पर दबाव बना रखा है जबकि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की निष्क्रियता के चलते पार्टी परेशान है।

इन दिनों में मध्यप्रदेश में पार्टी की कद्दावर नेता उभा भारती भाजपा से नाराज चल रही है। पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत का निमंत्रण नहीं मिलने पर उन्होंने दिग्गज नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उमा ने साफ कहा था कि औपचारिकता तो निभा देते, भले ही धीरे से आने के लिए मना कर देते। मैं नहीं आती। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनवाई तो हमने भी बीजेपी को एक पूरी सरकार बनाकर दी थी। निमंत्रण देने की औपचारिकता तो पूरी कर देते। उमा ने यह भी कहा कि, जब पार्टी को जरूरत

थी तो कोरोना पॉजिटिव होने के 11 दिन बाद ही उनको उपचुनाव में प्रचार के लिए बुला लिया गया जबकि उनकी रिपोर्ट तब तक निगेटिव भी नहीं आई थी। इस दौरान उमा 2024 का चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया और ये भी कहा कि शिवराज अगर कहेंगे तो ही प्रचार करूंगी। हाल ही में उमा ने विधानसभा चुनाव में अपने 19 समर्थकों के लिए टिकट की दावेदारी ठोंकी है। उमा भारती लोधी समुदाय से आती हैं और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक में लोधी समुदाय बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। मंडल और कमंडल की सियासत के दौर में लोधी समुदाय ओबीसी का एकलौता वोट बैंक था, जो बीजेपी के साथ खड़ा था। इसके पीछे लोधी समुदाय से आने वाले बीजेपी की दिग्गज नेता कल्याण सिंह और उमा भारती की अहम भूमिका रही थी।

राजस्थान की राजनीति में भाजपा का पर्याय बन चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी में अपना सियासी कद बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। लंबे समय से हाईकमान और राजे के बीच उठापटक की खबरें सामने आ रही है। यह पहली बार है कि विधानसभा चुनाव के लिए बनी सभी अहम कमेटियों से राजे गायब हैं। पार्टी के पोस्टरों से भी वसुंधरा का चेहरा नदारद है। जन्मदिन की रैली और धार्मिक यात्रा के जरिए राजे अपनी ताकत जरुर एहसास करने से भी नहीं चूक रही है।

दरअसल, भाजपा इस बार प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से बचते हुए दिखाई दे रहे है। पार्टी सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले,पीएम मोदी के नाम और काम वोट मांग रही है। लेकिन राजे को मैनेज करने के लिए भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी की रैली हो या फिर अमित शाह की हर जगह मंच पर वसुंधरा नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब राजस्थान के सांसदों के साथ बैठक की, तब भी वसुंधरा को बुलाया गया। एक तरफ पार्टी पूर्व सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रही और दूसरी तरफ मैनेज भी कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रदेश 200 में सीटों में राजे करीब 65 सीटों पर सीधा प्रभाव रखती हैं। राजपूत और जाट वोटर्स पर उनका अच्छा प्रभाव है। जाति-समुदाय की भावना से ऊपर उठकर हर जाति-वर्ग की महिलाओं में भी वो बहुत लोकप्रिय हैं।

छत्तीसगढ़ में भाजपा फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही हैं। अमित शाह आए दिन प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि कई बड़े नेताओं ने सूबे में डेरा डाल लिया है। पार्टी के दिग्गज नेता जरुर सक्रिय दिख रहे हो लेकिन प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे। इसे लेकर लगातार पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, पूर्व सीएम सिंह की पकड़ अब न जनता पर उतनी मजबूत रही और न ही पार्टी पर। तीसरे कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। रमन सिंह की ऐसी छवि बन गई कि उनकी सरकार अफसरशाही चला रही है। इससे बीजेपी को चुनाव में इसका नुकसान भी उठाना पड़ा और पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई। रमन सिंह के पास अपना कोई खास वोट बैंक नहीं है। इसलिए पार्टी भी जानती है कि उनके एक्टिव होने से पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए नेतृत्व भी उन्हें ज्यादा तरजीह देने से बच रहा है।

कांग्रेस की जातिवादी रणनीति के बीच कर्नाटक में लिंगायत वोक्कालिगा गठबंधन

अजय सेतिया

वैसे तो लोकसभा चुनाव आते आते न जाने कितने मुद्दे आएंगे और जाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण शाश्वत मुद्दा है। जबसे कर्नाटक में ईसाई दलितों और मुस्लिमों के समीकरण ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई है, तब से कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया है कि चुनावों का सारा खेल जातीय समीकरणों का है। इसलिए उसने जातीय जनगणना को मुद्दा बना लिया है, जबकि कांग्रेस हमेशा से जातीय जनगणना के खिलाफ रही थी।

जबसे भाजपा ने उत्तर भारत में हिन्दुओं की सभी जातियों को हिंदुत्व की छतरी में लाने में सफलता हासिल की है, तबसे यूपी-बिहार में जाति आधारित दलों और कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। इसलिए जाति आधारित दलों का एक ही एजेंडा है कि किसी तरह पिछड़ी जातियों को हिंदुत्व की छतरी से बाहर निकाला जाए। यह बात कर्नाटक में भाजपा को भी समझ आ गई है कि जातीय समीकरणों का ठीक होना ही चुनाव जीतने की कुंजी है। कर्नाटक में कई बड़े लिंगायत नेताओं की नाराजगी का भाजपा को विधानसभा चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ा। कर्नाटक के वोक्कालिगा और अल्पसंख्यक वोटर जेडीएस और कांग्रेस में बंटते थे, इसलिए भाजपा का पलड़ा भारी हो जाता था। इस बार के चुनाव में मुसलमानों ने जेडीएस का साथ छोड़कर सिर्फ कांग्रेस को चुना। ईसाई तो मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ थे ही, धर्मांतरण करके ईसाई बने दलितों ने भी कांग्रेस का साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस उन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का समर्थन करती है। वोक्कालिगा वोटरों को जब लगा कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, तो वे भी काफी तादाद में कांग्रेस के साथ चले गए। यह खेल देवेगौड़ा को चुनावों के बाद समझ में आया। अब जब उन्हें पता चल गया है कि अल्पसंख्यक वोटर उन्हें छोड़ गया है, उनके साथ सिर्फ वोक्कालिगा ही बचा है, तो देवेगौड़ा ने भाजपा से हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता कर्नाटक की थी, क्योंकि 2019 में उसे 28 में से 25 सीटें मिलीं थी, जिसे बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। पिछले दिनों भाजपा और जेडीएस में बातचीत शुरू हुई थी, बात एक नतीजे पर पहुंच भी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत नेता येदीयुरप्पा ने सहमति का एलान भी कर दिया था, लेकिन जेडीएस से खंडन किया गया था। भाजपा ने जेडीएस को लोकसभा की चार सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन भाजपा ने उसे सोचने का पूरा समय भी दिया था। आखिर शुक्रवार को एच. डी. कुमारस्वामी अपने बेटे के साथ दिल्ली आकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर एनडीए में शामिल हो गए।

लालू यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को समझा दिया है कि जब तक उत्तर भारत की पिछड़ी जातियां, दलित और आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होते, तब तक भाजपा को नहीं हराया जा सकता। जबसे ये सभी जातियां हिंदुत्व की छतरी के नीचे एकजुट हुई हैं, तबसे यूपी और बिहार के जाति आधारित दलों और कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। पिछड़ी जातियों को भाजपा से तोड़ने की रणनीति के तहत ही लालू यादव और नीतीश कुमार का दुबारा

गठबंधन हुआ है। पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण और उनकी वास्तविक जनसंख्या का पता लगाने के लिए जातीय जनगणना का दांव भी इन दोनों ने इसीलिए चला था। इंडी एलायंस की मुम्बई बैठक में जातीय जनगणना को एजेंडे में शामिल करवाने के लिए कांग्रेस, राजद, जेडीयू और सपा में सहमति हो चुकी थी। लेकिन ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल ने विरोध कर दिया। बाद में कांग्रेस ने एलायंस की को-ऑर्डीनेशन कमेटी से जातीय जनगणना को इंडी एलायंस के एजेंडे में शामिल करवा लिया। ममता बनर्जी इससे खफा हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी हैदराबाद बैठक में जातीय एजेंडे को अपने एजेंडे में शामिल करके ममता, उद्धव और केजरीवाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है।

हालांकि जातीय जनगणना हो या महिला आरक्षण इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस का खुद का राजनीतिक इतिहास दागदार है। ओबीसी पर कांग्रेस का इतिहास तो ऐसा है कि नेहरू के जमाने में काका कालेलकर की रिपोर्ट दबा दी गई और इंदिरा गांधी-राजीव गांधी के जमाने में मंडल आयोग की रिपोर्ट दबा दी गई। कांग्रेस ने हमेशा जाति आधारित जनगणना का विरोध किया था। आज़ाद भारत में जवाहर लाल नेहरू सरकार ने जाति आधारित जनगणना बंद करवा दी थी। 1951 की पहली जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना हुई, क्योंकि संविधान ने इन दोनों वर्गों को आरक्षण दिया था। आज़ादी के बाद अब तक सात बार जनगणना हुई है। इनमें से पांच बार 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 में कांग्रेस के राज में जनगणना हुई। किसी भी जनगणना में कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग स्वीकार नहीं की। 2001 को छोड़कर 2011 में फिर कांग्रेस की रहनुमाई वाली यूपीए सरकार में जनगणना हुई। तब यूपीए सरकार लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव के समर्थन पर टिकी थी। इन तीनों ने मनमोहन सिंह पर जातीय आधारित जनगणना का दबाव बनाया। मनमोहन सिंह ऑन रिकार्ड कह चुके हैं कि गठबंधन सरकार में उन्हें सिद्धांतो से समझौता करना पड़ा। उन्होंने सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के इस सिद्धांत से भी समझौता किया। लालू, मुलायम के दबाव में 2011 की जनगणना में जाति पूछी गई। लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े जाहिर नहीं किए गए। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार वे आंकड़े जारी करे, जो उनकी सरकार ने जारी नहीं किए थे। जातीय जनगणना के अलावा कांग्रेस के हाथ दूसरा मुद्दा लगा है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल दो मोर्चों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। एक तो उनकी मांग वही है, जिसे 2010 में कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। कांग्रेस का बिल इसी लिए लोकसभा में पास नहीं हो पाया था, क्योंकि लालू यादव, मुलायम सिंह और शरद यादव ने आरक्षण में ओबीसी वर्ग की महिलाओं का कोटा रखने की मांग कर दी थी। जातीय जनगणना और महिला आरक्षण में ओबीसी का आरक्षण लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और नीतीश के पुराने मुद्दे थे। कांग्रेस इन दोनों मुद्दों पर इन सभी जातीय आधारित राजनीति करने वालों के खिलाफ थी, लेकिन अब कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों को अपना लिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग को जोरदार ढंग से उठाया। लेकिन 8 मार्च 2010 को यूपीए सरकार के कांग्रेसी क़ानून मंत्री वीरप्पा मोईली ने राज्यसभा में कहा था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का कोटा संभव ही नही है। राहुल गांधी तब कांग्रेस महासचिव थे। अब वही राहुल गांधी महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग कर रहे हैं। महिला आरक्षण का दूसरा मुद्दा है कि बिल पास करवाने के लिए तो जल्दबाजी में संसद सत्र बुलाया गया और आरक्षण लागू करने की तारीख को जनगणना और डीलिमिटेशन से जोड़ दिया, जो न जाने कब होगी।

महाभारत एक पूर्ण न्यायशास्त्र है

मुझे ऐसा लगता है महाभारत एक पूर्ण न्यायशास्त्र है, और चीर-हरण उसका केन्द्र बिन्दु!

इस प्रसङ्ग के बाद की पूरी कथा इस घिनौने अपराध के अपराधियों को मिले दण्ड की कथा है। वह दण्ड, जिसे निर्धारित किया भगवान श्रीकृष्ण ने और किसी को नहीं छोड़ा...। किसी को भी नहीं।

दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखा कर अपनी जंघा ठोकी थी, तो उसकी जंघा तोड़ी गयी। दु:शासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गयी।

महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया, तो श्रीकृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया।

भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंध कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया, तो असँख्य तीरों में बिंध कर अपने पूरे कुल को एक-एक कर मरते हुए भी देखा...।

भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने चार पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब-तक सब देख नहीं लिया, तब-तक मर भी न सके... यही उनका दण्ड था।

धृतराष्ट्र का दोष था पुत्रमोह, तो सौ पुत्रों के शव को कंधा देने का दण्ड मिला उन्हें। सौ हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका।

दण्ड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था। दण्ड पांडवों को भी मिला।

द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे, तो सबसे कठोर दण्ड भी उन्ही को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्ही के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई।

अर्जुन रोते रहे, पर तीर चलाते रहे... क्या लगता है, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों, भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या ? नहीं... वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दण्ड था।

युधिष्ठिर ने स्त्री को दाव पर लगाया, तो उन्हें भी दण्ड मिला।

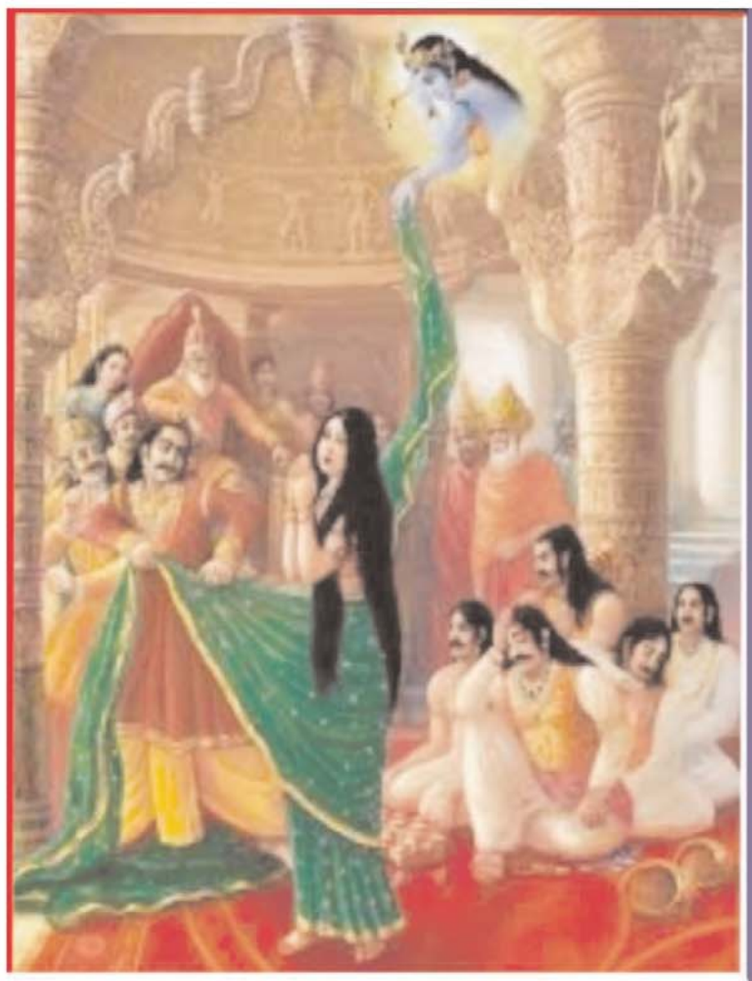

देवकी के बाल पकड़े कंस ने, और द्रौपदी के बाल पकड़े दु:शासन ने। श्रीकृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दण्ड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो...।

"चीरहरण उसका केन्द्र बिंदु"

कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्धभूमि में झूठ बोला, और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई।

यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा... धर्मराज के लिए इससे बड़ा दण्ड क्या होगा ?

दुर्योधन को गदायुद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदायुद्ध की शिक्षा देने का दण्ड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाह कर भी कुछ न कर सके...

उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दण्ड दे सकते थे, कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया, और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया।

लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का बध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दण्ड नहीं मिल पाता।

कृष्ण युद्धभूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरें थे, कृष्ण कृष्णा के अपराधियों को दण्ड दिलाने उतरे थे।

कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमामण्डन किया है। पर सुनिए! कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र-हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किये गये सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि वह महानीच व्यक्ति था, और उसका वध ही धर्म था।

स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जायजाय। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बाल से पकड़ कर घसीटा गया।

देवकी के बाल पकड़े कंस ने, और द्रौपदी के बाल पकड़े दु:शासन ने। श्रीकृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दण्ड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो...।

यही न्याय है, यही धर्म है। और इस धर्म को स्थापित करने वाला भारत है, सनातन है...।

मायावी ग्रह राहु अक्टूबर में बदलेंगे अपनी राशि

इन राशियों का शुरू होगा शुभ समय

ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु दोनों मायावी और रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं. राहु और केतु 18 माह में राशि परिवर्तन करते हैं. वर्तमान में राहु मेष राशि में विराजमान हैं, जोकि 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में गोचर करेंगे ।

राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को शाम 04 बजकर 37 मिनट पर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में में राहु 18 मई 2025 को तक रहेंगे। 18 मई 2025 को शाम 07 बजकर 35 मिनट में राहु मीन से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु के साथ ही केतु वर्तमान में तुला राशि में हैं। 30 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि में केतु का गोचर होगा।

राहु के गोचर का सभी राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष के अनुसार, ऐसी तीन राशियां हैं, जिन्हें राहु के गोचर से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। राहु की चाल बदलने पर इन राशियों के जीवन में चल रही मुश्किलें कम हो जाएंगी। जानते हैं इन राशियों के बारे में।

राहु का गोचर इन राशियों के लिए शुभ

मेष राशि :- वर्तमान में राहु मेष राशि में हैं और गुरु ग्रह भी मेष राशि में हैं। ऐसे में मेष राशि में गुरु चांडाल दोष का निर्माण हुआ है। लेकिन राहु के मीन राशि में प्रवेश करते ही मेष राशि वालों को इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी और गुरु ग्रह मेष राशि वालों पर अपनी कृपा बरसाने लगेंगे।

वृषभ राशि :- राहु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। निवेश में लाभ होगा और धन संचय में वृद्धि होगी। आप इस समय अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाने में प्रयास करते दिखेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लंबे समय रुके काम भी इस समय पूरे होंगे। राहु के शुभ प्रभाव से आपकी चुनौतियों में कमी आएगी।

कन्या राशि :- राहु का मीन राशि में गोचर करना कन्या राशि वालों के जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस समय अप्रत्याशित धन का लाभ हो सकता है और जीवन में खुशहाली आएगी। कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

मकर राशि :- मकर राशि वालों के लिए जीवन में राहु के गोचर से सकारात्मक परिणाम आएंगे। आय वृद्धि के लिए नई संभावनाएं मिलेगी और आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर राहु का गोचर मकर राशि वालों की परेशानियों को कम करने वाला साबित होगा।

संतान सप्तमी कल

पुत्र प्राप्ति के लिए ये उपाय करना न भूलें

पुत्र प्राप्ति की चाह रखने वालों के लिए संतान सप्तमी का व्रत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस साल संतान सप्तमी 22 सितंबर 2023 को है। इसे ललिता सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है।

मान्यता है कि जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित है उन्हें ये व्रत करना चाहिए, इसके प्रभाव से जल्द सूनी कोंध भर जाती है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिये किया जाता है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा का मुहूर्त और उपाय।

संतान सप्तमी 2023 मुहूर्त

भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि शुरू – 21 सितंबर 2023 को दोपहर 02 बजकर 14

भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तिथि समाप्त – 22 सितंबर 2023 को दोपहर 01 बजकर 35

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04:35 – सुबह 05:22

अभिजित मुहूर्त – सुबह 11:49 – दोपहर 12:38

गोधूलि मुहूर्त – शाम 06:18 – शाम 06:42

अमृत काल – सुबह 06:47 – सुबह 08:23

संतान सप्तमी उपाय

संतान सुख के लिए - संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं बच्चे का सुख नहीं भोग पा रही हैं वह निर्जला व्रत रखकर भोलेनाथ को सूती का डोरा अर्पित करें। संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करें, पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण करें। मान्यता है इससे संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। निसंतान दंपत्ति को बच्चे का सुख मिलता है।

बच्चे के अच्छे करियर के लिए - संतान की सुख-समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है।

इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर शाम के समय शिव पार्वती को गुड़ से बने 7 पुए का भोग लगाएं। मान्यता है इससे संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं खत्म होती है। उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर करियर प्राप्त होता है।

संतान को मिलेगी दीर्घायु - संतान सप्तमी पर व्रती सूर्य को अर्घ्य दें और फिर शिव जी को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को नारियल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती हैं और उनके सभी दुखों का नाश होता है।

गणेश जी को क्यों प्रिय है मोदक

गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। 10 दिन तक चलने वाले गणेशोत्सव में मोदक का प्रसाद चढ़ाने पर बप्पा की विशेष कृपा बरसती है। क्या आप जानते हैं गणपति को मोदक इतना प्रिय क्यों है, जानें रोचक कथा।

मोदक

कैसे बना गणपति का प्रिय व्यंजन ?

* जब परशुराम जी के वार से गणपति का दांत टूट गया तो उन्हें भोजन ग्रहण करने में कापी दिक्कत आने लगी। तब माता पार्वती ने उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मुलायम मोदक बनाए। मोदक खाने से गणपति बहुत खुश हुए, तभी से ये उनका प्रिय व्यंजन हो गया।

* जब परशुराम जी के वार से गणपति का दांत टूट गया तो उन्हें भोजन ग्रहण करने में कापी दिक्कत आने लगी। तब माता पार्वती ने उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मुलायम मोदक बनाए। मोदक खाने से गणपति बहुत खुश हुए, तभी से ये उनका प्रिय व्यंजन हो गया।

* एक बार गणपति परिवार संग अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसूया के घर गए। गणेश जी ने अपना सारा भोजन खत्म कर लिया, भंडार भी खाली हो गए लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरा तो माता अनुसूइया ने उन्हें मीठे-मीठे मोदक परोसे। इसे खाने के बाद गणपति बहुत खुश हुए और उनका पेट भी भर गया। इस कारण गणपति को मोदक पसंद है।

* मोद का अर्थ खुशी होता है। गणपति जी सदा प्रसन्न रहने वाले देवता माने गए हैं। यही वजह है बप्पा की पूजा में मोदक जरुर चढ़ाया जाता है।

* मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को मोदक का भोग लगाने से रोग, शोक, दुख, दरिद्रता का नाश होता है।

बुलंद रहे धर्म की पताका

धर्म एक आदत के समान है। इसका स्वयं पालन करना आवश्यक है, लेकिन दूसरों को पालन करवाने के लिए ज़बरदस्तीकरना नहीं चाहिए। धर्म का विस्तार धर्म के अनुसार ही होना आवश्यक है यदि आप धर्म के विस्तार के लिए अधर्म कर रहे हैं तो आपका धर्म पहले ही नष्ट हो चुका है। धर्म का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिस समाज में धार्मिक व्यक्ति निवास करते हैं वहाँ अधर्म अपने आप समाप्त हो जाता है। धर्म व्यक्ति के मष्तिष्क से मोह-माया को समाप्त कर उन्हें जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत करवाता है। धर्म विश्वास पर आधारित है कृपया इसका आधार अंधविश्वास को ना बनाएँ। धर्म की उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई है मानव हानि के लिए नहीं। अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से पालन करना ही अपने धर्म को निभाना है। मानव धर्म सभी धर्मों से ऊपर है। उपरोक्त बातों पर गहन विचार करने के बाद हमें लगा कि आज-कल के भाग-दौड भरे जीवन में पर्व और तिथियाँ याद रखना चुनौती बन गया है। इसलिए आपकी चुनौती का समाधान करने का बीडा हमने उठाया है। इसके तहत पाठकों को प्रतिदिन के व्रत-त्योहार की जानकारियाँ एक जगह समेट कर आपके समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं।

– संजना अग्रवाल

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी आज देश को देंगे नौ वंदे भारत का तोहफा

हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को देशवासियों को एक साथ नौ वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा देंगे। पीएम मोदी दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) की दो सेवाओं सहित नौ वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया। बयान के अनुसार, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये काचीगुडा-यशवंतपुर और विजयवाड़ा-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल मार्गों के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार, काचीगुडा-यशवंतपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा इस मार्ग की अन्य ट्रेनों की तुलना में कम से कम यात्रा समय के साथ दोनों शहरों के बीच सबसे तेज ट्रेन होगी। इसमें 530 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। विजयवाड़ा - एमजीआर चेन्नई सेंट्रल मार्ग पर ट्रेन इस मार्ग पर पहली और सबसे तेज ट्रेन होगी।

ईवीएम नहीं बैलट पेपर से कराए जाएं लोस चुनावः तिवारी

नई दिल्ली। कांग्रेस राज्यसभा सांसद मनीष तिवारी ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए बैलट पेपर पर 2024 के लोस चुनाव कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के भरोसे इतने कीमती लोकतंत्र प्रक्रिया को नहीं छोड़ा जा सकता है। मनीष ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी है, बल्कि सवाल यह है कि ईवीएम से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह पर्याप्त कारण है कि अब बैलट पेपर पर ही अगले लोकसभा चुनाव होने चाहिए। साथ ही मनीष तिवारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी आखिरकार एक मशीन ही है। फिर, वोटिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कर बोला कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, हेराफेरी की जा सकती है और मशीन को वोट डालने के दौरान भी रोका भी जा सकता है और यही नहीं ईवीएम से खिलवाड़ करना भी बहुत आसान है।

ओबीसी को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी को दिया जवाब

नईदिल्ली। राहुल गांधी ने शुक्रवार को खेद व्यक्त किया कि यूपीए सरकार ने अपने महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी उप-कोटा पेश नहीं किया था, और स्वीकार किया। इसके बाद वह भाजपा के निशाने पर आ गए है। भाजपा लगातार उनसे सवाल कर रही है। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैंने कल राहुल गांधी का बयान सुना...कांग्रेस स्वभाव से ओबीसी विरोधी रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही ओबीसी आयोग बनाया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी। उन्होंने नीट और नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण दिया। आप दशकों तक सत्ता में थे और तब आपने कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कहा कि इनके अनुसार देश सचिव चलाते हैं, हमारे अनुसार देश सरकार चलाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को लेकर कैबिनेट निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में 29 प्रतिशत सांसद ओबीसी के हैं। तुलना करना है तो आ जाइए... मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया गया।

आप ने हरियाणा में बढ़ाई कांग्रेस के लिए मुश्किलें

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। इस बात की जानकारी राज्य इकाई के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने दी। उन्होंने कहा कि पार्टी का पूरा संगठनात्मक ढांचा तैयार है और जल्द ही अपनी ग्राम-स्तरीय समितियों की भी घोषणा करेगी। हालाँकि, ढांडा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए, भारतीय विपक्षी गुट के सदस्यों के बीच सीट बंटवारे पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। यह दूसरा मौका है पार्टी की ओर से इस तरह का दावा किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कोई समझौता नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा और आप सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के लिए हम पार्टी आलाकमान के आदेश का पालन करेंगे। आप नेता से वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा की हालिया टिप्पणी के बारे में पूछा गया था कि उनकी पार्टी अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जीतने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस अगले साल के आम चुनाव में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई नोटिस नहीं मिला : उदयनिधि

चेन्नई। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उन्हें अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नोटिस नहीं मिला है, जिसमें शनिवार को सनातन धर्म टिप्पणी के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार और उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था। अपनी सनातन धर्म टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मैंने मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में देखा। स्पष्टीकरण मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार के अलावा एमपी ए राजा, एमपी थिरुमावलवन, एमपी सु वेंकटेशन, तमिलनाडु के डीजीपी ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पीटर अल्फोंस और अन्य को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में रखी क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला, बोले-

यह स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान जैसा

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इसके लिए प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम, जो पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है, आधुनिक, विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उनके दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा। पीएम मोदी ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। इस दौरान सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री, बीसीसीआई सचिव जय शाह और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी उपस्थित रहे।

इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं, जब चंद्रमा के शिवशक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का एक महीना पूरा हो रहा है। एक शिवशक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिवशक्ति का स्थान यहां काशी में है। उन्होंने कहा कि काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान जैसा होगा। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के पूरा होने पर 30,000 से ज्यादा लोग यहां बैठकर मैच देख पाएंगे। जबसे इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई है, उन्हें देखकर हर काशीवासी गदगद हो गया है।

मोदी ने कहा कि आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि जब मैचों की संख्या बढ़ेगी तो नए स्टेडियमों की जरूरत भी पड़ेगी। तब बनारस का ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। ये पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ सितारा बनने वाला है। उन्होंने कहा कि आज जिस स्टेडियम(अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम) की आधारशिला रखी गई है, ये स्टेडियम बस ईंट और कंक्रीट से बना एक मैदान नहीं बल्कि भविष्य के भारत का एक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि आज से एशियन गेम्स की शुरुआत हो रही है और मैं गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मोदी ने दावा किया कि 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट तीन गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70त्न की वृद्धि की गई है।

गांजरी, राजातालाब में बनने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण पर 121 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस परियोजना पर लगभग 331 करोड़ रुपये खर्च करेगा। स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरणा लेती है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट और घाट सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था के लिए डिज़ाइन विकसित किए गए हैं। स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों को बैठाने की होगी और इसके निर्माण में कम से कम 30 महीने लगेंगे।

प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया

नईदिल्ली। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी सभा को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा भारत ने हाल ही में आजादी के 75 साल पूरे किए। आजादी की लड़ाई में, कानूनी बिरादरी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कई वकीलों ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। दुनिया आज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कानूनी बिरादरी किसी भी देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्षों से, न्यायपालिका और बार भारत की कानून व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। पीएम मोदी ने आज कहा, मजबूत, निष्पक्ष न्याय प्रणाली 2047 तक भारत को विकसित बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के सम्मेलन में पीएम ने कहा, महिला आरक्षण कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को नई दिशा, ऊर्जा देगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 23 सितंबर (शनिवार) और 24 सितंबर (रविवार) को न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना

नयी संसद को जयराम रमेश ने बताया मोदी मल्टीप्लेक्स

जेपी नड्डा बोले- कांग्रेस की दयनीय मानसिकता

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक बार फिर केन्द्र सरकार पर हमला किया है। जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। रमेश ने कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद नए संसद का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इधर, जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के निम्नतम मानकों के हिसाब से भी यह एक दयनीय मानसिकता है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। नड्डा ने कहा कि वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी काम कर रही है।

गौरतलब है कि नये संसद भवन को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। साथ ही बीजेपी की ओर से भी वार पर पलटवार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रमेश ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इतने प्रचार के साथ लॉन्च किया गया नया संसद भवन वास्तव में पीएम के उद्देश्यों को अच्छी तरह से साकार करता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। रमेश ने कहा कि मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत और बातचीत खत्म हो गई थी। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को मार सकती है, तो संविधान को दोबारा लिखे बिना भी प्रधानमंत्री पहले ही सफल हो चुके हैं।

अपने ट्वीट में रमेश ने पुराने और नये संसद भवन की तुलना की है। रमेश ने कहा कि नये भवन में एक-दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत होगी, क्योंकि हॉल बिल्कुल आरामदायक या कॉम्पैक्ट नहीं है। पुराने संसद भवन की न केवल एक विशेष आभा थी बल्कि यह बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता था। सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच चलना आसान था। यह नया संसद के संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। दोनों सदनों के बीच त्वरित समन्वय अब अत्यधिक बोझिल हो गया है। पुरानी इमारत में, यदि आप खो गए थे, तो आपको अपना रास्ता फिर से मिल जाएगा क्योंकि यह गोलाकार था। नई इमारत में, यदि आप रास्ता भूल जाते हैं, तो आप भूलभुलैया में खो जाते हैं। पुरानी इमारत आपको जगह और खुलेपन का एहसास देती है जबकि नई इमारत लगभग क्लौस्ट्रफ़ोबिक है।

रमेश ने कहा कि संसद में घूमने का आनंद गायब हो गया है। मैं पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइनों से परे मेरे कई सहकर्मी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से यह भी सुना है कि नए भवन के डिजाइन में उन्हें अपना काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यात्मकताओं पर विचार नहीं किया गया है। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के साथ कोई परामर्श नहीं किया जाता है।

गौरतलब है कि नये संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इस दौरान भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। हालांकि कांग्रेस सहित 20 विपक्षी पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार किया था।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे आज

इंदौर। भारतीय टीम रविवार को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए तैयार है। मैच दोपहर 1.30 बजे होना है। शुक्रवार को पहले वनडे में, मेन इन ब्लू ने 48.4 ओवर में 277 रन के लक्ष्य का आसानी से पीछा किया और पांच विकेट से गेम जीत लिया। इस जीत के दम पर उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए, अनुभवी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अच्छी फॉर्म दिखाई और वह अपनी लय जारी रखना चाहेंगे। पिछली बार जब वनडे मैच इंदौर में खेला गया था, तब भारत ने रोहित और शुभमन गिल के शतकों की मदद से न्यूजीलैंड के खिलाफ 385 रन बनाए थे। यह देखना दिलचस्प होगा कि रविवार को क्या होता है। मोहाली में सपाट विकेट पर रन बनाने से चूकने वाले श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कुछ रन अपने नाम पर जोड़ने का प्रयास करेंगे जबकि स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बीच के ओवरों में विकेट हासिल करने के लिए बेताब होंगे।

भारत- के एल राहुल (कप्तान), रविंद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, इशान किशन, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज , प्रसिद्ध कृष्णा।

ऑस्ट्रेलिया- पैट कमिंस (कप्तान), एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, एडम ज़म्पा, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जोश हेज़लवुड, स्पेंसर जॉनसन, मार्नस लाबुशेन, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांघा, मैट शॉर्ट।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

भविष्य में सेमीकंडक्टर की मांग पांच लाख करोड़ रु. पर पहुंचेगी

नई दिल्ली। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन ने 23 सितंबर (शनिवार) को गुजरात के साणंद औद्योगिक क्षेत्र में 2.75 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र के पहले चरण के निर्माण को हरी झंडी दिखाने के लिए एक ग्राउंडब्रेकिंग समारोह आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि कहा कि अगले छह महीनों में अहमदाबाद और साणंद के बीच एक हाई-स्पीड ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन के संयंत्र के शिलान्यास समारोह में वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें साणंद में भी रुकेंगी। उन्होंने कहा, अहमदाबाद से साणंद के बीच एक विश्व स्तरीय ट्रेन शुरू होगी। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हुए, वैष्णव, जिनके पास संचार और आईटी विभाग भी है, ने कहा, अगले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर की मांग बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपये होने जा रही है।

इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री को नहीं मिल रही गति

नईदिल्ली। इस महीने की शुरुआत में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गर्व से भारत में फलते-फूलते इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण उद्योग के बारे में बताया था। उन्होंने अब तक 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचने को उपलब्धि करार देते हुए इसमें 600 से अधिक स्टार्टअप कंपनियों की भूमिका पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि साल 2030 तक बर साल 1 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होगी। देश में शांति से हो रही ईवी क्रांति काफी प्रशंसनीय है मगर आंकड़ों के पीछे की कहानी आशाजनक नहीं है। एक विश्लेषण से पता चलता है कि देश में 640 कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बनाती हैं। लेकिन 345 कंपनियों ने बताया कि उन्होंने 100 से कम गाड़ियां बेची हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 से 10 लाख वाहनों की बिक्री में शीर्ष 20 कंपनियों की 70 फीसदी हिस्सेदारी रही।

निरमा का होगा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में हिस्सेदारी

नई दिल्ली। डिटर्जेंट साबुन बनाने वाली कंपनी निरमा ने ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 7,500 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर 75 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स ने 615 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जो कि समेकित रूप से 5,650 करोड़ रुपये होता है की कीमत पर ग्लेनमार्क लाइफसाइंसेज में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए निरमा लिमिटेड के साथ शेयर खरीद समझौता किया है। यह लेनदेन ग्लेनमार्क लाइफसाइंसेज के वर्तमान बाजार मूल्य की तुलना में मामूली 2 प्रतिशत छूट के साथ हुआ है। इस बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स के बकाया ऋण को चुकाने के लिए किया जाएगा, जो वित्त वर्ष 2023 तक 4,340 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, निदेशक मंडल लेनदेन को अंतिम रूप देने से पहले 2,250 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार कर रहा है।

महंगाई कम होने का असर तीसरी तिमाही से दिखेगा

नईदिल्ली। पिछले साल की तुलना में जिंसों की कीमतों में नरमी का सितंबर तिमाही से डाबर इंडिया पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कंपनी के अनुसार, लेकिन मंहगाई में नरमी का पूरा लाभ अगली तिमाही में ही देखने को मिलेगा। घरेलू सामान बेचने वाली कंपनी को भी उम्मीद है कि त्योहारी सीजन अच्छा रहने से दिसंबर तिमाही में उसकी वृद्धि को मदद मिलेगी। डाबर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, 'पिछले साल की तुलना में रुझान काफी बेहतर है। यह बहुत सकारात्मक है, लेकिन त्योहारों में देरी का असर इस तिमाही पर पड़ेगा।' उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन को पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा, 'पिछले साल महंगाई अधिक रहने के कारण त्योहारी सीजन पर काफी असर पड़ा था। इसके उलट इस साल रुझान अच्छे दिख रहे हैं।

एशियाड में क्या सच होगा 100 के पार का नारा, पिछली बार 70 पर अटक गए थे

मनोज चतुर्वेदी

चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से शुरू हुई एशियाई खेलों में भारत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की आस लगाए हुए है। इस बार सौ पार का नारा दिया गया है। यानी भारत सौ से ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद कर रहा है। भारत ने पांच साल पहले जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में 16 स्वर्ण सहित 70 पदक जीते थे। इसका मतलब है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए सौ पदकों का आंकड़ा पार करना चुनौतीपूर्ण होगा। एशियाई खेलों जैसे आयोजन में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, जिनसे स्वर्णिम प्रदर्शन की आस होती है। इस बार ऐसे स्टार खिलाड़ियों में जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, बॉक्सर निकहत जरीन, पहलवान बजरंग पूनिया, स्टीपलचेजर अविनाश साबले, शटलर सात्विक साईराज-चिराग शेट्टी की जोड़ी, एचएस प्रणय, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना शामिल हैं।

नीरज चोपड़ा की तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई अन्य भारतीय एथलीट धाक नहीं जमा सका है। उन्होंने पिछली विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ अपने नाम एक ऐसा रेकॉर्ड दर्ज कराया, जिसे इससे पहले कोई भारतीय नहीं कर सका था। वह विश्व चैंपियनशिप और ओलिंपिक के साथ डायमंड लीग फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले इकलौते भारतीय बने। चोपड़ा एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत सकते हैं। लेकिन इसके साथ वह 90 मीटर की लाइन भी पार करना चाहेंगे। उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर का रहा है।

भारत का 3000 मीटर स्टीपलचेज में प्रतिनिधित्व करने वाले अविनाश साबले ने भी पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

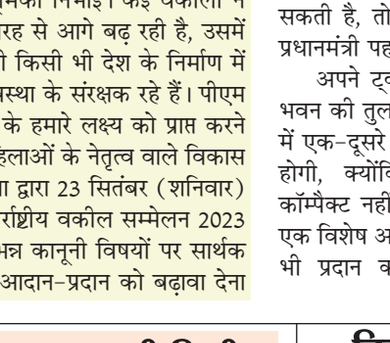

सफलताएं हासिल करके देश का नाम रोशन किया है। वह कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता हैं। वह यदि अपना सर्वश्रेष्ठ समय निकाल सके तो उनसे भी गोल्ड की उम्मीद की जा सकती है। लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर और जेस्विन एल्ड्रिन में भी चमक बिखेरने का माद्दा है। वैसे, इस बार एथलेटिक्स का सबसे बड़ा 68 सदस्यीय दल भाग ले रहा है और पदक की संख्या सौ पार पहुंचाने में इसकी ही सबसे अहम भूमिका रहने वाली है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पिछले दिनों भारत को मोरक्को पर जीत दिलाने के बाद डेविस कप से संन्यास ले लिया। वह इस साल जबर्दस्त फॉर्म में हैं और पिछले दिनों साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में पुरुष डबल्स के फाइनल तक चुनौती पेश कर चुके हैं। इसलिए वह अपने आखिरी एशियाई खेलों को स्वर्णिम प्रदर्शन के साथ अलविदा कहना चाहेंगे। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यदि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहरा सकीं तो उनके गोल्ड जीतने की राह में कोई बाधा नहीं आएगी। निकहत जरीन विश्व चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। निकहत के सफल करियर में पिता मोहम्मद जमील की भी अहम भूमिका है। मोहम्मद जमील कहते हैं कि हर किसी को अपनी राह बनानी पड़ती है और निकहत ने भी ऐसा ही किया है। बजरंग पूनिया भी नीरज की तरह स्टार खिलाड़ी का दर्जा रखते हैं। लेकिन वह पिछले दिनों मैट पर किए प्रदर्शनों के बजाय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ संघर्ष को लेकर ज्यादा सुर्खियों में थे। उनके सामने चुनौती होगी कि वह जकार्ता में जीते गोल्ड के बाद फिर से स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा पाते हैं या नहीं।

सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी भारतीय बैडमिंटन इतिहास की पहली जोड़ी है, जिसे बीडब्ल्यूएफ 1000 सीरीज का खिताब जीतने का गौरव हासिल है। यह जोड़ी पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के साथ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इस जोड़ी की मौजूदा विश्व रैंकिंग दूसरी है और उनके स्वर्ण के साथ लौटने का भरोसा है। इस बार कुछ युवाओं के स्टार के रूप में चमकने की उम्मीद की जा सकती है। इनमें महिला पहलवान अंतिम पंघाल और एथलीट शैली सिंह शामिल हैं।

भाजपा की दूसरी लिस्ट 28 सितंबर के बाद

चर्चा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट 28 सितंबर के बाद जारी हो सकती है। 28 सितंबर को

परिवर्तन यात्रा का बिलासपुर में समापन होना है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। इसके बाद दूसरी सूची आ सकती है। माना जा रहा है दूसरी लिस्ट में करीब 52 लोगों के नाम हो सकते हैं। भाजपा पहले ही 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि 2018 में हारी हुई 52 सीटों के लिए ही भाजपा पहले प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। खबर है कि भाजपा हाईकमान ने नामों को अंतिम रूप दे दिया है , घोषणा भर बाकी है। वैसे पहले घोषित 21 उम्मीदवारों में से कइयों के नाम पर स्थानीय स्तर पर अब भी बवाल मचा हुआ है। कुछ जगह लोग खुलकर सामने आ गए हैं तो कहीं-कहीं दबी जुबान से बात कर रहे हैं।

कही-सुनी

रवि भोई

आसमान में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट

कांग्रेस की प्रभारी महासचिव कुमारी सैलजा ने पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट छह सितंबर को जारी करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सितंबर बीतने को जा रहा है और अब तक लिस्ट का अता-पता नहीं हैं। प्रत्याशियों के नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा भी हो चुकी थी। केंद्रीय चुनाव समिति का मुहर लगना बचा था। कहते हैं कांग्रेस ने मंत्रियों और पक्की जीत की संभावना वाले विधायकों को टिकट देने का मन बना लिया है , फिर भी भाजपा की बराबरी करने में कांग्रेस पीछे क्यों हट रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चर्चा है कि कुछ मंत्री इस बार चुनाव क्षेत्र बदलना चाहते हैं, इस कारण कांग्रेस की लिस्ट आसमान में लटकी हुई है।

अजब-गजब कलेक्टर साहब

कहते हैं एक कलेक्टर साहब से नेता-पत्रकार सभी परेशान हैं। ये साहब किसी का फोन नहीं उठाते। यहां तक कांग्रेसी नेताओं के भी मोबाईल नहीं उठाते। अब जिले के मुखिया राजनेताओं के फोन नहीं उठाएंगे, तो उनकी दुकान चलेगी कैसे ? कलेक्टर साहब पत्रकारों को भी भाव देते नहीं हैं। चर्चा है कि सत्ता में बैठे एक ताकतवर नेता के मुंह लगे होने के कारण कलेक्टर साहब किसी की परवाह नहीं करते। एक कलेक्टर साहब ऐसे हैं कि लोगों के ज्ञापन लेने में भी भय खाते हैं। पिछले दिनों एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी के पड़ोस के जिले में धरना कर कलेक्टर साहब से मिलकर ज्ञापन सौंपने की बात कही तो उन्होंने दो टूक कह दिया, हमारे जिले में तो एडीएम साहब ही ज्ञापन लेते हैं। नेताजी ने जब पूछा कलेक्टर साहब का काम क्या तो उन्होंने फोन काट दिया। अब कलेक्टर नेताओं के फोन नहीं उठाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं तो जनता का दर्द क्या समझेंगे ?

राजभवन से खुश नहीं भाजपा नेता

कहते हैं भाजपा के कुछ नेता राजभवन से खुश नहीं हैं। कुछ नेता ऐसे हैं कि अब भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के साथ राजभवन जाने से मना करने लगे हैं। चर्चा है भाजपा के नेता राज्यपाल महोदय को कई मुद्दों पर ज्ञापन सौंपकर सरकार के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं को एक्शन नजर नहीं आ रहा है। खबर है कि कुछ समय पहले राजभवन से जुड़े एक अफसर भाजपा के कुछ नेताओं को महामहिम से मिलने से रोक रहे थे। बाद में ये नेता पूर्व मुख्यमंत्री से अप्रोच लगवाकर राजभवन जा सके। वैसे राजभवन से जुड़े अफसर से महामहिम से मिलने जाने वाले भी दुखी बताए जाते हैं। आम लोग महामहिम से एकांत में अपना दर्द बयां करना चाहते हैं, पर वे साये की तरह जमे रहते हैं।

भाजपा नेताओं का फटा गुस्सा

कहते हैं पिछले दिनों भाजपा की कई समितियों से जुड़े नेताओं का गुस्सा फट पड़ा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग-अलग कामों के लिए समितियां गठित कर दी है। इसमें क्रय समिति , वित्त समिति,स्वागत समिति, वाहन समिति और भी कई समितियां हैं। चर्चा है कि पिछले दिनों समिति के पदाधिकरियों की बैठक हुई। बैठक में अलग-अलग समितियों के पदाधिकारी एक साथ भड़क उठे। चर्चा है कि सभी पदाधिकारी इस बात से खफा थे कि उनसे पूछे बिना सब काम कर लिया जाता है , फिर समिति और उन्हें पदाधिकारी बनाने का औचित्य क्या है ? बड़े नेताओं ने आगे उनकी पूछपरख बढ़ाने का आश्वासन तो दिया है,देखते हैं आगे क्या होता है।

क्या यही है परिवर्तन ?

भाजपा 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली हुई है। खबर है कि परिवर्तन यात्रा वाहन में छत्तीसगढ़ की जगह राजस्थान का नक्शा प्रिंट करवा दिया गया। लोग कह रहे हैं क्या यही परिवर्तन है। इस पर बवाल मचने के बाद सुधरवाया गया। कहा जा रहा है परिवर्तन यात्रा वाहन पर नक्शा बनवाने वाले एक शख्स रायपुर उत्तर से टिकट के दावेदार हैं। लोग मजे ले रहे हैं कि इस शख्स को टिकट मिल गया और जनता ने उन्हें चुन लिया तो ये विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जगह राजस्थान की बात करने लगेंगे। खबर है कि नक्शा बनवाने में भूमिका निभाने वाले एक शख्स का वास्ता राजस्थान से है। लोग चुटकी ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रहकर ये अभी तक शायद राजस्थान को भूल नहीं पाए हैं।

छत्तीसगढ़ पीएससी फिर सुर्ख़ियों में

छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग एक बार फिर सुर्ख़ियों में है। इस बार गलत चयन को लेकर नहीं, बल्कि भाई-भतीजावाद को लेकर। पीएससी के कर्णधारों ने नैतिकता को खुटी में टांगकर पदों को अपने रिश्तेदारों के बीच बांट दिया। कुछ महीने पहले भी मामला उठा था , लेकिन जोर पकड़ नहीं पाया था। इस बार मामला हाईकोर्ट तक पहुँच जाने से तूल पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ पीएससी शुरू से चर्चा में रहा है , लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। सरकार गड़बड़ी की जांच कराने की बात कर रही है। अब किससे कराएगी, इसका खुलासा नहीं किया है। पीएससी एक संवैधानिक संस्था है। यहां से चयनित राज्य की मशीनरी के अंग होते हैं। मशीन के कलपुर्जे ही गुणवत्ता वाले नहीं होंगे तो सिस्टम ठीक से कैसे काम चलेगा, यह बड़ा सवाल है?

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक हैं।)

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

महिला आरक्षण बिल महिलाओं से धोखा -दीपक बैज़

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि आरक्षण का संघर्ष इस देश की महिलाओं के लिए बहुत लंबा रहा है और हर बार उनको मायूसी ही झेलनी पड़ी है। इस बार जब महिला आरक्षण बिल आया तो सशक्तिकरण और

राजनीतिक भागीदारी की उम्मीद एक बार फिर जागी। लेकिन आज देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ऐसा लग रहा है, मुँह तक आया निवाला ही छीन लिया गया हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि आनन-फ़ानन में लाए गए इस बिल के ज़रिये महिलाओं को आखिर आरक्षण कब मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। सरकार ख़ुद कह रही है 2029 से पहले संभव ही नहीं। जनगणना और परिसीमन से महिला आरक्षण को जोड़कर, महिलाओं को कहा गया है - अभी इंतज़ार लंबा है। सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 82 - 81(3) का हवाला दिया जिसके अनुसार 2026 का परिसीमन उसके बाद वाली जनगणना मतलब 2031 वाली जनगणना पर ही संभव है। यानी महिला आरक्षण संभवत: 2039 तक ही हो सकता है ।आखिर 2024 में ये क्यों नहीं हो सकता? अगर वाक़ई में इच्छाशक्ति है तो जैसे दो मिनट के अंदर नोटबंदी, तीन काले क़ानून, लॉकडाउन, 370 को हटाने जैसे निर्णय लिए गए थे - वो अब भी लिये जायें। अगर इस क़ानून से महिलाओं को वाक़ई सशक्तिकरण और भागीदारी देने की मंशा है।

मोदी शाह आ गये लेकिन जनता को ट्रेन नही मिल रहा: ठाकुर

रायपुर । रेलवे द्वारा फिर यात्री ट्रेनों को रद्द करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को ट्रेन की सुविधा दिलाने के लिए कांग्रेस ने आंदोलन किया तब भाजपा के सांसद आंदोलन के

खिलाफ बयानबाजी कर रेलवे की काली करतूत को पर्दा करने में लगे थे। अब रेलवे ने फिर कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है।तब भाजपा के बयानवीर सांसदो के मुंह में दही जमा है रेलयात्रियों की समस्यों पर दो लाईन बोलने की साहस नही कर पा रहे है। दुर्भाग्य की बात है भाजपा के प्रचार करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी रेल यात्रियों के समस्याओं पर मौन थे और मोदी सरकार के दर्जनों मंत्री बीते 6 माह से छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं लेकिन रेल यात्रियों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। रेलवे अडानी की मालगाड़ी ट्रेनों को चलाने के लिए जनता की ट्रेनों को रद्द कर रही है और मेंटेनेंस का हवाला दे रही है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है अगर मेंटेनेंस के चलते हैं यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है फिर मालगाड़ी ट्रेन उस ट्रैक पर कैसे चल रही है? रेलवे कब तक झूठ बोलकर अडानी कि मालगाड़ी को बेरोक टोक चलाएगी और मुनाफा कमायेगी? लोकल ,एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन रद्द होने से आम जनजीवन प्रभावित होता है। आम लोग समय पर यात्रा नहीं कर पाते हैं किसी के सुख-दुख में शामिल नहीं हो पा रहे हैं डीजल पेट्रोल की कीमतों में हुई मनमानी वृद्धि सड़कों यात्रा के दौरान लगने वाला भारी भरकम टोल टैक्स के चलते यात्रा इतनी महंगा हो गया है।

परिवर्तन यात्रा केवल बाहरी नेताओं के भरोसे: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के परिवर्तन यात्रा और चुनावी सभा के लिए आज छत्तीसगढ़ आए 6-6 केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर

तंज कसते हुए कहा है कि अपनी विश्वसनीय खत्म हो जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता नए-नए केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर उनसे लगातार झूठ बुलवाने का काम कर रहे हैं। मैनपुर में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बेरोजगारी और अपराध के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ की जनता को अपमानित किया। वादाखिलाफी भाजपा का राष्ट्रीय चरित्र है, अपराध में नंबर वन भाजपा शासित राज्य है, छत्तीसगढ़ तो 18वें क्रम पर है भूपेश सरकार में अपराध लगातार नियंत्रित हुए हैं और सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य तो छत्तीसगढ़ है। केंद्रीय मंत्री यह भूल गए कि रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत हुआ करता था, जो भूपेश सरकार आने के बाद लगातार कम हुआ है। विगत 1 साल से छत्तीसगढ़ देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है, आधा फ़ीसदी से भी कम बेरोजगारी दर है छत्तीसगढ का। लेकिन दलिय चाटुकारिता में देश के केंद्रीय मंत्री बेशर्मी से झूठ बोल कर छत्तीसगढ़ की जनता को अपमानित कर रहे हैं। भूपेश पर भरोसे की सरकार के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के सारे पैंतरे नाकाम हो चुके हैं।

डेयरी संचालन से समूह की महिलाएं बनी सक्षम उद्यमी

रायपुर। दूरस्थ क्षेत्रों के महिलाएं, पशुपालक आज आजीविका से जुड़कर सशक्त हो रही है। उन्हें गांव में ही रोजगार मिलने से महिलाओं ने खुशी जाहिर की। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर और राजपुर में स्व सहायता समूह की महिलाएं डेयरी व्यवसाय से जुड़कर दूध उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इसका सीधा लाभ आस पास के सभी पशुपालकों को हो रहा है। रीपा के तहत दूध इकाई स्थापित होने से महिला उघमिता को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में दो समूह में महिलाएं मिलकर दूधवाला नाम से डेयरी संचालन कर रही है। महिलाओं ने बताया कि गांव के आस पास के पशुपालकों से दूध खरीदकर दूध तथा दूध से निर्मित खाघ पदार्थो का विक्रय कर रही हैं। महिलाओं और पशुपालकों को बाजार मिलने से उनकी आय मे वृद्धि हो रही है। योजना के शुरुआती चरण में वाड्रफनगर और राजपुर में दूध संग्रहण केंद्र खोले गए है, जिसमें विभिन्न समूह की 70 महिलाएं दूध संग्रहण और वितरण का कार्य कर रही हैं। समूह की महिलाओं के द्वारा आस-पास के 10 गावों के 76 पशुपालकों से लगभग 152 लीटर दूध की खरीदी नियमित रूप से की जा रही है। समूह की महिलाओं द्वारा नगरीय क्षेत्र के 136 उपभोक्ताओं को प्रतिदिन बिहान मार्ट के द्वारा दूध का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही बचे हुए दूध से समूह की महिलाएं विभिन्न प्रकार के मिठाईयां तैयार कर रहीं हैं। साथ ही बचे हुए दूध से मिठाइयों का निर्माण कर उन्हें बेचकर अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। सदाबहार समूह की सदस्य श्रीमती मीना बताती है कि महिलाओं को मिलाकर एक उत्पादक समूह का गठन किया गया है।

नारी शक्ति वंदन विधेयक एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक: गोमती साय

रायपुर। सांसद श्रीमती गोमती साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़निश्चयी व संकल्पवान नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन विधेयक के संसद में पारित होने को एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक बताते हुए कहा है कि भारत की मातृ शक्ति के इस अप्रतिम सम्मान से लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ है।उन्होंने कहा कि संसद का नया भवन इस विधेयक के रूप में नई ऊर्जा, नए विश्वास और संकल्पों के सृजन का साक्षी बना है। सांसद श्रीमती गोमती साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे शासनकाल में लोगों के साथ, माता और बहनों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आज प्रधानमंत्री श्री मोदी के सक्षम नेतृत्व व निर्णायक नेतृत्व के कारण नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद में पारित हो गया है। नारी के सम्मान की दृष्टि इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। इस विधेयक के पारित होने के बाद निश्चित रूप से न केवल दिल्ली में, बल्कि पूरे देश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है और खुशियाँ मना रही हैं। देश की माताओं-बहनों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को आशीर्वाद देते हुए इस बात पर गर्व किया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नारी शक्ति का सचमुच में वंदन किया है। सांसद श्रीमती गोमती साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वह अब जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा तय करने की बात कर रही है।

एक साथ 5 केंद्रीय मंत्री पहुंच गए रायपुर

मनसुख मांडविया का महिलाओं ने किया स्वागत, भानूप्रताप बोले अब सीजी में 20 साल रहेगी भाजपा सरकार

रायपुर। शनिवार को प्रदेश में 5 केंद्रीय मंत्री पहुंचे। एक ही दिन में इन ङ्कढ्ढक्क्च्य के मूवमेंट से रायपुर एयरपोर्ट में दिनभर गहमा गहमी रही। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और अन्य केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी स्वागत समिति के लोकेश कावड़िया, संजय यादव, प्रितेश गांधी, मीनल चौबे जैसे नेताओं ने इन सभी का स्वागत किया। रायपुर एयरपोर्ट पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने की खुशी में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का विशेष स्वागत महिलाओं ने किया। मांडविया के अलावा केंद्रीय बिजली राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय जल शक्ति जनजाति कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू पहुंचे।

इनके अलावा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची। पहले से ही कार्यक्रमों में लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय केंद्रीय राज्यमंत्री भानूप्रताप वर्मा शामि रहे। ये सभी केंद्रीय मंत्री परिवर्तन यात्रा की सभाओं में शामिल हुए और प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस पर जमकर बरसे।

क्या बोले मोदी कैबिनेट के मंत्री

गरियाबंद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय केंद्रीय राज्यमंत्री भानूप्रताप वर्मा ने कहा- 15 साल तक इस छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार चली है। 2018 के बाद यहां अब जब कांग्रेस आई तो आज परिवर्तन की जरुरत है। जब 2003 में ऐसी ही परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में निकली तो जनता ने भाजपा को जिम्मा सौंपा।

2023 की ये परिवर्तन यात्रा फिर एक बार कह रही है कि जनता भाजपा को चुने। अब जो भाजपा सरकार आएगी वो 20-25 साल चलेगी। क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं दी हैं वो सबसे अच्छी हैं। मगर ये सुविधाएं छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के कारण नहीं मिल पा रही।

डभरा की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली शामिल हुए। तेली मूलतः छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। लंबे समय से असम में भाजपा के झंडे तले राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सभा में कहा- मेरा परिवार मजदूरी करने असम गया था, लोगों ने प्यार दिया। मैं 26 साल की उम्र में विधायक बना। पिछले असम चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता असम गए वहां खूब पैसे खर्च किए मगर रिजल्ट जीरो रहा।

तेली ने आगे कहा- मैं एक बार फ्लाइट से आ रहा था तो छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू मिले। 2018 में साहू समाज के लोगों से कहा गया कि ताम्रध्वज सीएम बन सकते हैं यही कहकर धोखे से वोट ले लिया गया मगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। जनता को इस तरह से फुसलाकर वोट लेकर सरकार बना ली गई है।

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल ने कहा- भारत के लोग भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाने का फैसला करें। 2014 से पहले भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में चूर-चूर हो चुकी थी। लेकिन लोगों ने देश में परिवर्तन किया तो दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। तो छत्तीसगढ़ का डंका पूरे भारत में बजवाना चाहते हैं तो 2023 में प्रदेश में परिवर्तन करना होगा।

अन्नपूर्णा देवी ने कहा - नल, जल, आयुष्मान योजना जैसी सुविधा आज भाजपा की वजह से देश की जनता को मिल रही है। शिक्षा अच्छी मिली, क्योंकि केंद्र में लोगों ने भाजपा को चुना सरकार बनाई। इस वजह से देश को सशक्त सरकार मिली। देश में बदलाव हुए। छत्तीसगढ़ की जनता भी बदलाव करेगी। छत्तीसढ़ में शराब, रेत, अन्न योजना की लूट हो रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। बहुमत से भाजपा की सरकार बनानी है और देश में मोदी सरकार बनानी है।

परिवर्तन यात्रा बीते 12 दिनों से जारी है। इसमें पीयूष गोयल, असम के सीएम हिमंत बिस्वा, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जैसे दर्जनों नेता पहुंच चुके हैं। यात्रा उन इलाकों में भी फोकस कर रही है जहां कांग्रेस की पैठ है। भाजपा 21 सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर चुकी है। उन्हें भी मंच पर लाकर उनके लिए वोट अपील की जा रही है। हिंदुत्व, भ्रष्टाचार जैसे मामलों में कांग्रेस को घेरकर छत्तीसगढ़ की सियासी जमीन पर 15 साल की सत्ता से 15 सीट पर सिमटी भाजपा अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की पुरजोर कोशिश में है।

रीपा में स्थित तेल मिल प्रोसेसिंग यूनिट से समूह की महिलाएं हो रही हैं सशक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत बने गौठानों में संचालित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) से ग्रामीणों एवं महिलाओं की जिन्दगी संवर रही है। रीपा से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के सकारात्मक और बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। ग्रामीण और महिलाएं अब खुद हुनरमंद होकर छोटे-छोटे रोजगार के जरिए स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर होने लगे हैं।

नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत कोलियारी (नेतानार) के रीपा में वहां की महिलाओं द्वारा तेल मिल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया है। जिसमें बजरंगी स्व-सहायता समूह की 10 सदस्यों को रीपा से जोड़कर तेल मिल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेंसिंग एवं पैकेजिंग संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के उपरान्त बजरंगी स्व-सहायता के समूह के द्वारा आसपास के किसानों से तिलहन फसल खरीद कर उसे प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग कर बाजार में बड़ी मात्रा में बिक्री किया जा रहा है। तेल की उत्तम गुणवत्ता के कारण दिनों-दिन इसकी मांग बाजार में

बढ़ती जा रही है। समूह द्वारा अब तक 600 लीटर तेल की पैकिंग की जा चुकी है, जिसकी कीमत प्रति लीटर 250 रूपये है। समूह के द्वारा अब तक 1 लाख 50 हजार रूपये तक के तेल की बिक्री की जा चुकी है। पहले समूह के सदस्य माह में एक से 15 सौ रूपये ही कमा पाते थे, लेकिन आज प्रत्येक सदस्य की मासिक आय 6 हजार रूपये तक हो गई है। इस समूह को वर्तमान में लगभग 10 लाख रूपये तक के तेल का आर्डर मिल चुका है। बजरंगी समूह की महिलाओं का कहना है कि तेल प्रोसेसिंग यूनिट कार्य के साथ-साथ हम अपने घर के कृषि कार्य व मनरेगा का भी काम करती हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य को करते हुये हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अच्छी आमदनी प्राप्त होने से परिवार के भरण-पोषण में सहयोग मिल रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना रीपा का शुभारंभ किया था। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इन पार्कों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। प्रत्येक रीपा के विकास के लिए दो करोड़ रुपए आबंटित किए गए। योजना के अंतर्गत गौठानों को महात्मा गांधीरूरल इंडस्ट्रियल पार्क से जोड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है। ग्रामीणों को आय में वृद्धि करने के नए स्त्रोत मिल पा रहे है जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। गाँव में उद्यमिता को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहे हैं, जिससे लोगों को अब रोजी मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता।

एसआई-प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर भर्ती में गड़बड़ी

याचिकाकर्ताओं की अंतरिम अर्जी हाई कोर्ट ने की खारिज

बिलासपुर। प्रदेश में एसआई-प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर भर्ती में गड़बड़ी को लेकर लगाई गई याचिका पर याचिकाकर्ताओं की अंतरिम अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले में 700 प्रतियोगियों की ओर से दायर 122 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने बंद लिफाफे में अपना जवाब प्रस्तुत किया है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था. 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षार्थियों ने गड़बड़ियों को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई.

हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए अंतरित राहत नहीं दी थी, लेकिन राज्य सरकार को गड़बड़ियों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2023 के आदेश के तहत पहले ही खारिज कर दिया है. इसलिए अब भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने वाला कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है.

12वे दिन परिवर्तन यात्रा पहुंची मैनपुर

देश को एक गरीब मां का बेटा चला रहा है : साव

रायपुर। मैनपुर में पहुंची परिवर्तन यात्रा की भव्य आमसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा केंद्र की सरकार को एक गरीब मां का बेटा चला रहा है वो गरीब का दर्द जानते है यही कारण है आज हमारे पड़ोसी प्रदेश से एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति के पद पर पहुंच चुकी है। आज भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लोगो को मूर्ख समझकर प्रदेश के लोगो को गेड़ी चलाना , कांटे वाला चम्मच में बासी खाना सीखा रहे है छत्तीसगढ़ के लोग मेहनती है ,ईमानदार है बेवकूफ नही है वो गेड़ी चढ़ना भी जानते है,बासी खाना भी जानते है आपने विकास

के काम करना चाहिए थे जो आपने नही किए। जिसने छत्तीसगढ़ के लोगो को लुटा उस कांग्रेस से बदला लेने का समय आ गया है प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आकर बड़े बड़े भाषण देती है जब वो छत्तीसगढ़ आई तो एडिशनल एसपी के ऑफिस की पार्किंग में नाबालिक के साथ बलात्कार हो रहा था भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के लिए गुलाब के फूल बिछाते है लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाते। उन्होंने कहा भूपेश बताए कांग्रेस विधायको के पास जो नोट के बंडल दिख रहे है वो कौन से घोटाले के है कोयला,शराब या चावल घोटाला? *अगर छत्तीसगढ़ का डंका पूरे देश में बजवाना चाहते है तो भाजपा को वोट दें- कृष्णपाल गुर्जर* मैनपुर में परिवर्तन यात्रा की आमसभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार के मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने कहा कांग्रेस राज मे छत्तीसगढ़ बेरोजगारी में नंबर 1,अपराध ने नंबर वन 1, वादाखिलाफी में नंबर 1 है मोदी जी का भेजा अन्न भी कांग्रेसी खा गए इंसान तो इंसान गाय के गोबर का पैसा भी खा गए। ऐसी सरकार को छत्तीसगढ़ के हित के लिए हटाना ही होगा। कांग्रेस राज ने हम सब कुछ दूसरे देशों से मंगवाते थे आज मोदी राज में हम दूसरे देशों को सामान बेचते है। मोदी जी न होते तो 370 धारा नही हट सकती थी,राम मंदिर नही बनता, देश का विकास न होता ।मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार विकास के नए कीर्तिमान बनाएगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.